सांध्य दैनिक

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534

डाक पंजीयन क्र.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 182 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, गुरूवार 16 अप्रैल 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

आरटीई : निजी विद्यालयों में भर्ती के लिए ऑनलाइन लॉटरी से 14 हजार 403 विद्यार्थियों का चयन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बुधवार को आरटीई अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की चयन सूची जारी की गई। यह प्रक्रिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की उपस्थिति में सम्पन्न कराई गई।

इस वर्ष कुल 21 हज़ार 975 सीटों के विरुद्ध 38 हजार 439 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27 हजार 203 आवेदन पात्र एवं 11 हज़ार 236 आवेदन अपात्र पाए गए। पात्र आवेदनों में से 14 हजार 403 विद्यार्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया है। यह चयन संख्या मुख्यमंत्री डी.ए.व्ही. विद्यालयों की आरटीई सीटों को छोड़कर है।

जिलेवार चयनित विद्यार्थियों का विवरण

जिलेवार चयनित विद्यार्थियों की स्थिति इस प्रकार है- रायपुर में 2606, बिलासपुर में 1509, दुर्ग में 1059, कोरबा में 534, राजनांदगांव में 480, बलौदाबाजार-भाटापारा में 457, जांजगीर-चांपा में 500, मुंगेली में 702, कवर्धा में 367, धमतरी में 354, बलरामपुर में 798, रायगढ़ में 544, बेमेतरा में 315, जशपुर में 543, सक्ती में 347, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 258, महासमुंद में 244, कांकेर में 471, बालोद में 353, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 195, सूरजपुर में 427, सरगुजा में 273, गरियाबंद में 193, कोरिया में 179, बस्तर में 135, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 206, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 112, कोंडागांव में 101, नारायणपुर में 35, मोहला- मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 48, दंतेवाड़ा में 35, सुकमा में 9 तथा बीजापुर में 14 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

खास-खबर

चार करोड़ के दबाव में व्यापारी ने पत्नी-बच्चों संग जहर खाया, हालत गंभीर

कबीरधाम। जिले के कवर्धा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवा व्यापारी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या का प्रयास किया। व्यापारी, उसकी पत्नी और दो बच्चों ने जहर का सेवन किया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना करीब चार करोड़ रुपये के भारी लेन-देन और आर्थिक तंगी से जुड़ी है।व्यापारी पर भारी उधारी का दबाव था और उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। इसी मानसिक तनाव के कारण उसने परिवार सहित यह खौफनाक कदम उठाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस को घटनास्थल से तीन पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला है। इस नोट में व्यापारी ने अपनी आर्थिक परेशानियों और लेन-देन की पूरी स्थिति का विस्तार से जिक्र किया है। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल सभी पीड़ितों का अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

बीजापुर में अतिक्रमण पर सख्ती, सड़क चौड़ीकरण के लिए 74 लोगों को नोटिस

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीतजापुर जिले के भोपालपटनम नगर में लंबे समय से नेशनल हाईवे के किनारे जमे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाने में जुट गया है। जिला मुख्यालय के चट्टान पारा में हाल ही में हुए बुलडोजर एक्शन के बाद भोपालपटनम प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था और भविष्य में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार लक्ष्मण कुमार राठिया ने बुधवार को 74 मकान और दुकान मालिकों को नोटिस जारी कर पेशी पर तलब किया है। प्रशासन के इस कड़े रुख से नगरवासियों में चर्चा का माहौल है। व्यापारियों द्वारा सड़कों पर शेड निकालना और मकान मालिकों द्वारा नालियों के ऊपर अवैध पक्का निर्माण करने से शहर की स्थिति खराब हो गई है। सूचना मिलते ही कई दुकानदारों ने जल्दबाजी में अपना सामान हटाना शुरू कर दिया।

महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश

■ विपक्ष ने किया विरोध, काले कपड़े पहनकर पहुंचे डीएमके सांसद

नईदिल्ली। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल गुरूवार को संसद में पेश किए गए। इन बिलों में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 2029 से 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है। इसके लिए तीन दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। संसद मे बिल पेश होने से पहले ही विपक्ष ने विरोध का मन बना लिया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डीएमके सांसदों ने विरोध शुरू किया। डीएमके सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। तमिलनाडु में सीएम एमके स्टालिन ने विधेयक की प्रति जलाकर विरोध दर्ज कराया।

संसद के विशेष सत्र में गुरूवार को सरकार ने तीन अहम विधेयक लोकसभा में पेश करने की प्रक्रिया शुरू की। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 को सदन में पेश करने का प्रस्ताव रखा। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 को पेश करने का प्रस्ताव दिया। इन बिलों पर लोकसभा में आज से 18 घंटे की चर्चा शुरू होगी। इन बदलावों के बाद देश की संसद में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। संविधान में संशोधन की तैयारी के लिए बुलाए गए तीन दिवसीय विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी ने कहा कि देश नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है।

विधेयक पेश करने हुई वोटिंग

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 2026 को पेश करने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें अधिकतर सांसदों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया। विधेयक के पक्ष में 251 वोट और विरोध में 185 वोट पड़े। विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक को पेश करने के फैसले के खिलाफ मतविभाजन (वोटिंग) की मांग की थी, लेकिन वोटिंग में सरकार का पलड़ा भारी रहा।

850 सांसद होंगे

संशोधन बिल में लोकसभा सांसदों की संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। मौजूदा संख्या 543 है। राज्यों में 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 तक सीटें होंगी। सीटों की सटीक संख्या तय करने के लिए परिसीमन भी किया जाएगा। 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

गृहमंत्री शाह ने कहा- धर्म के आधार पर नहीं होगा आरक्षण

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेताओं के बयानों पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की। इस पर शाह ने कहा समाजवादी पार्टी सभी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दें तो हमें क्या आपत्ति होगी। वहीं अखिलेश यादव ने जनगणना को लेकर भी सवाल उठाया था।

सरकार ने शुरू कर दी है जनगणना की प्रक्रिया

अमित शाह ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार पहले ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। अमित शाह ने बताया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है और इसमें जाति से जुड़ा डेटा भी एकत्र किया जा रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर फैसला उनके हाथ में होता तो वे घर-घर में जाति तय करने की प्रक्रिया तक ले जाते।

रायपुर के टिंबर मार्केट में भीषण आग रातभर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के फाफाडीह स्थित टिंबर मार्केट में बुधवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आग पायनियर मार्केटिंग के कैलाश टिंबर गोदाम में शुरू हुई और देखते ही देखते आसपास के हिस्सों तक फैल गई।

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। शुरुआत में कुछ गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए संख्या बढ़ाकर 12 से अधिक फायर ब्रिगेड वाहनों को तैनात करना पड़ा। दमकल कर्मियों ने पूरी रात मशक्कत करते रहे।

आग पर नियंत्रण पाने के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ी। इसके लिए एम्स अस्पताल परिसर से पानी लाकर आग बुझाने में उपयोग किया गया। लगातार प्रयासों के बावजूद आग ने गोदाम में रखे बड़े पैमाने पर लकड़ी और प्लाईवुड को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों और धुएं के कारण आसपास के व्यापारियों में दहशत का माहौल रहा।

दो भाइयों ने युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। अंडा थाना क्षेत्र स्थित खाड़ा गांव में शराब के नशे वाद विवाद के बाद हुए मारपीट के बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर पहुंचकर मृतक के शव को पीएम के लिए भेजकर हत्या करने वाले 2 भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है।

अंडा थाना क्षेत्र के खाडा गांव में 12 अप्रैल की रात शंभू निषाद अपने दोस्तों से मिलने गया था। जहां शराब की पार्टी किए और शराब के नशे में मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को बात को लेकर वाद विवाद हो गया। विवाद में दोनों ने शंभू की जमकर पिटाई कर दी। घायल अवस्था में शंभू अपने घर में जाकर सो गया। सुबह तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए भेजकर आरोपियों संतोष यादव और रोहित यादव को गिरफ्तार किया है।

खराब बीज पर कंपनी को झटका, फसल बर्बादी पर भरना होगा हर्जाना

श्रीकंचनपथ न्यूज

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ में किसानों के पक्ष में एक अहम फैसला सामने आया है। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीज कंपनी नोबेल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की तीनों अपीलों को खारिज कर दिया है और जिला उपभोक्ता आयोग, कबीरधाम के आदेश को बरकरार रखा है।

यह मामला कबीरधाम जिले के ग्राम बहरमुडा के तीन किसानों से जुड़ा है, जिन्होंने साल 2024 में 'नोबेल हैप्पी 101' फूलगोभी के बीज खरीदे थे। कंपनी ने इन बीजों से गर्मी में भी अच्छी पैदावार का दावा किया था, लेकिन खेतों में हालात इसके उलट निकले। किसानों के मुताबिक, आधे से ज्यादा पौधों में फूल ही नहीं आए, जबकि जो फसल तैयार हुई वह भी खराब गुणवत्ता की थी और बाजार में बेचने लायक नहीं थी। शिकायत के बाद उद्यानिकी विभाग की जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर बीज में खामी की पुष्टि की।

कंपनी ने मौसम को जिम्मेदार ठहराते हुए अपना बचाव किया, लेकिन आयोग ने इन दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने साफ कहा कि केवल अखबार की खबरों के आधार पर ओलावृष्टि का दावा साबित नहीं होता और आम किसान से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह सबूत के तौर पर बीज संभालकर रखे। फैसले के तहत तीनों किसानों को फसल नुकसान, खर्च और मानसिक पीड़ा के एवज में लाखों रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही, तय समय में भुगतान नहीं होने पर कंपनी को ब्याज भी देना होगा।

चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी, दिखेंगे कई बदलाव

■ विशेष पूजा कराने के लिए लागू होंगी शुल्क की बढ़ी हुई दरें

देहरादून। चारधाम यात्रा को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को व्यवस्थाओं में कई बदलाव दिखेंगे। यात्रा का आगाज 19 अप्रैल को गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से होगा। 22 अप्रैल को केदारनाथ व 23 अप्रैल को बदरीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से संचालित होगी।

सरकार ने इस बार चारधाम में प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। बीते वर्ष धामों में भीड़ नियंत्रण के लिए धारण क्षमता के आधार पर अधिकतम संख्या तय की गई थी। इस बार सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का प्लान बनाया है।

बदरी-केदार मंदिर समिति ने धामों की पवित्रता व दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर में लगने वाली भीड़ को देखते हुए मोबाइल फोन को प्रतिबंधित किया है। बदरीनाथ व केदारनाथ मंदिर में यह व्यवस्था लागू होगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा राज्य के अर्थव्यवस्था व रोजगार की रीढ़ है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड तैयार है। किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सुरक्षित व सुगम यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, जिससे वापस जाने के बाद देवभूमि के प्रति एक अच्छा संदेश लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री साय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन कर दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से दूरभाष पर बातचीत कर उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि श्री चौधरी के अनुभव, नेतृत्व क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण से बिहार में तीव्र प्रगति सुनिश्चित होगी।

छत्तीसगढ़ में हीट वेव, 43 डिग्री पहुंचा तापमान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ रही है। प्रदेश के मध्य हिस्सों में खासकर 16 से 19 अप्रैल के बीच बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग में लू (हीट वेव) का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ा है और अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंच चुका है।प्रदेश में फिलहाल मौसम पूरी तरह ड्राई बना हुआ है।

बीते 24 घंटों में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 43 डिग्री राजनांदगांव में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्रीअंबिकापुर में दर्ज हुआ। आने वाले 2 दिनों में भी मौसम शुष्क रहेगा और कुछ जगहों पर हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, दक्षिण-पूर्व मध्यप्रदेश से लेकर कोमोरिन तक फैली एक द्रोणिका और कर्नाटक-महाराष्ट्र के ऊपर बने प्रति चक्रवात के कारण प्रदेश में गर्मी का दबाव बढ़ रहा है। इसके चलते मध्य क्षेत्र में अगले दो दिनों के भीतर तापमान में 2 से 3 डिग्री तक और वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीटवेव यानी लू जैसी स्थिति बनने की पूरी संभावना है। खासकर मध्य क्षेत्र के में गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं।

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रियाई चांसलर स्टॉकर से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बात

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉ क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रिया के बीच आपसी रिश्तों को और मजबूत करना है। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

इससे पहले ऑस्ट्रिया के चांसलर स्टॉकर ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित किए। चांसलर स्टॉकर अपनी चार दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। साल 2025 में पद संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत और एशिया यात्रा है। बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चांसलर स्टॉकर से मुलाकात की थी। जयशंकर ने सोशल मीडिया पर खुशी जताते हुए कहा कि यह मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने वाली चर्चा से सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

चांसलर स्टॉकर जब बुधवार को भारत पहुंचे, तो हवाई अड्डे पर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बहुत ही दोस्ताना संबंध हैं। इस यात्रा से 'भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी' को और अधिक गति मिलेगी। चांसलर के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। इसमें कई बड़े कारोबारी, वरिष्ठ मंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रिश्तों को बढ़ावा देना है। दोनों देश मिलकर ग्रीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और हाई-एंड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में काम करने की योजना बना रहे हैं।

संपादकीय

बढ़ेगा गरीबी का दायरा

खाड़ी संघर्ष के असर से बढ़ी महंगाई की मार

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की पश्चिम एशिया युद्ध से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करने वाली रिपोर्ट के निष्कर्ष चिंता बढ़ाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी में ईरान-अमेरिकी युद्ध से उपजी परिस्थितियों के चलते भारत में और 25 लाख लोग गरीबी की दलदल में फंस सकते हैं। साथ ही मानव विकास की प्रगति में कुछ कमी आने की आशंका पैदा हो गई है। रिपोर्ट इस बात का भी खुलासा करती है कि पश्चिम एशिया में सैन्य गतिविधियों में वृद्धि से एशिया प्रशांत क्षेत्र में मानव विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट बताती है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से लोगों की घरेलू क्रयशक्ति घट रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है। वहीं विकास कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा आजीविका के अवसर कम हो रहे हैं। इस संकट में जहां पूरे विश्व में 88 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने की आशंका है, वहीं भारत में यह अनुमानित संख्या 25 लाख है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एशिया-प्रशांत में तकरीबन 299 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, भारत की बड़ी आबादी के सामने बढ़ने वाली गरीबों की संख्या छोटी है, लेकिन इससे भारत में गरीबी की दर बढ़ सकती है, जिसके 35.40 करोड़ होने की आशंका है। दरअसल, आज भी भारत करीब 90 फीसदी तेल जरूरतों के लिए आयात पर आश्रित है। हम कच्चे तेल का 40 फीसदी से अधिक और रसोई गैस का 90 फीसदी आयात पश्चिम एशिया से करते हैं। साथ ही हम अपने उर्वरकों का 40 फीसदी हिस्सा युद्धग्रस्त पश्चिमी एशिया से आयात करते हैं। एलएनजी की कीमतों में वृद्धि से कोयला आधारित बिजली पर हमारी निर्भरता बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर व्यापार व आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हुई। आशंका है कि संघर्ष से रेमिटेंस में भी कमी आएगी।

> “ रिपोर्ट बताती है कि ईंधन, मालभाड़ा और कच्चे माल की लागत बढ़ने से लोगों की घरेलू क्रयशक्ति घट रही है, जिससे खाद्य असुरक्षा भी बढ़ रही है। वहीं विकास कार्यों के लिए निर्धारित सरकारी बजट पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा आजीविका के अवसर कम हो रहे हैं। इस संकट में जहां पूरे विश्व में 88 लाख लोगों के गरीबी की चपेट में आने की आशंका है, वहीं भारत में यह अनुमानित संख्या 25 लाख है। रिपोर्ट में पश्चिम एशिया में तनाव के चलते एशिया-प्रशांत में तकरीबन 299 अरब डॉलर तक का नुकसान होने की आशंका है। हालांकि, भारत की बड़ी आबादी के सामने बढ़ने वाली गरीबों की संख्या छोटी है, लेकिन इससे भारत में गरीबी की दर बढ़ सकती है, जिसके 35.40 करोड़ होने की आशंका है।

निस्संदेह, मालभाड़ा शुल्क, युद्ध जोखिम बीमा, मार्ग परिवर्तन और देरी की वजह से आयातित तेल आदि की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिससे हमारे आयात मूल्य में वृद्धि व निर्यात का नुकसान बढ़ा है। असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। वहीं खाद की आपूर्ति में बाधा का असर खरीफ की फसल पर पड़ने की आशंका है। इस सब के चलते बढ़े दामों का प्रभाव आम आदमी की जेब पर हो रहा है, जिसका रोजगार और आय के मामले में असर बड़ी आबादी पर नजर आ रहा है। हाल ही में नोएडा और मानेसर में श्रमिक असंतोष को इसकी परिणति के रूप में महसूस किया जा सकता है। दरअसल, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो रही है। आर्थिक परेशानियों के चलते आम आदमी अब अपने जरूरी खर्चों में कटौती कर रहा है। वजह है उसकी आय के साधन सीमित होना। वहीं निम्न आय वर्ग के लोगों में इससे भरण-पोषण का संकट पैदा हो रहा है। श्रमिक असंतोष के बीच आक्रोश उभरा कि महंगाई के अनुपात में उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, फलत: जीवनयापन कठिन होता जा रहा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट में भी स्वीकार किया गया कि मार्च में खुदरा महंगाई बढ़कर 3.4 हो गई है, जिसकी वजह पश्चिमी एशिया से उपजा संकट बताया जा रहा है। सवाल यह है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास सिरे क्यों नहीं चढ़ रहे हैं। यदि कदम प्रभावकारी हैं तो फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। वास्तव में खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि को महंगाई का मुख्य कारण बताया जा रहा है। यद्यपि सरकार की दलील है कि खुदरा महंगाई दर केंद्रीय बैंक की रेड लाइन चार फीसदी से नीचे है। लेकिन वास्तव में स्थिर आय के चलते महंगाई अधिक महसूस की जा रही है। लेकिन लोगों की चिंता यह है कि यदि पश्चिम एशिया संकट का शीघ्र समाधान नहीं निकलता है तो महंगाई की मार असहनीय हो सकती है। यदि समय रहते सरकार की तरफ से ठोस प्रयास किए जाते हैं तो महंगाई पर अंकुश लगाना संभव हो पायेगा।

इस्लामाबाद वार्ता में प्रवाह के सिद्धांत की अनदेखी

लेफ्टिनेंट एसएस मेहता

पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से होर्मुज गतिरोध की बात करें तो दुनिया के संकरे द्वारों में निरंतर आवाजाही ही स्थिरता प्रदान कर सकती है। आपूर्ति श्रृंखलाएं, वित्तीय प्रणालियां और डिजिटल नेटवर्क वैश्विक प्रणाली की जीवन रेखाएं हैं। राजनीति इस प्रवाह की संरक्षक' बननी चाहिये। लेकिन इस्लामाबाद वार्ता में यह मिसाल कायम नहीं हो सकी।

आधुनिक दुनिया बात तो करती है शांति की, लेकिन व्यवहार करती है व्यवधान की मशीनरी के ज़रिए। युद्ध अब केवल सीमाओं या खंदकों तक सीमित नहीं; आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं, वित्तीय प्रणालियां थरथराती हैं और डिजिटल नेटवर्क एवं समुद्री मार्ग रुकते हैं। प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र हमारे अस्तित्व के हर पहलू तक फैल चुका है, लेकिन शासकीय सिद्धांत अभी भी 17वीं सदी के 'वेस्टफेलियन संप्रभुता' के तर्क में अटके हैं। हम बाड़ लगाने के औज़ारों से बाढ़ नियंत्रण में लगे हैं।

मूल अंतर्दृष्टि: निरंतरता के रूप में स्थिरता- इतिहास एक शांत सत्य उजागर करता है : स्थिरता निरंतर आदान-प्रदान होते रहने से बनती है, न कि प्रतिद्वंद्विता के अभाव से। मार्ग मुक्त रहें और आवाजाही सुरक्षित रहे, तो दुनिया समृद्ध होती है। जब ये प्रवाह थम जाए, तो पतन होता है। स्थिरता प्रवाह संग चलती है। यह हमारा गंतव्य न होकर वह गति है जिसे बनाए रखना होता है- जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शिनाख्त की थी, न कि आविष्कार। हमारे समय के व्यवधान एक अंतर्निहित नियम उजागर करते हैं : स्थिरता प्रवाह की निरंतरता के पीछे-पीछे आती है। यह तर्क कोई नया नहीं। भौतिकी इसे काफी पहले कायम कर चुकी है। प्रवाह को प्रतिरोध द्वारा संरक्षित किया व बनाया जाता है, और अंतर से प्रवाह काम करता है। एकदम बांध दें, तो दबाव कहीं और बन जाएगा। तोड़ दें, तो तबाही मच जाएगी। ग्लोबल सिस्टम का व्यवहार भी इससे अलग नहीं।

इस्लामाबाद वार्ता : मिसाल कायम करने का मौका गंवाया- इस्लामाबाद में बहुत बड़े दांवों वाली वार्ता में, मिसाल कायम करने का अवसर गंवा डाला। सप्ताहों तक बढ़ती गई तनातनी के बाद दोनों पक्ष मिले। अपनी-अपनी स्थिति का बचाव करते रहे, इतिहास का हवाला दिया, और रेड लाइंस खिंची। लेकिन वे खाली हाथ लौटे। जो कुछ हुआ, वह कोई वार्ता नहीं रही; यहां एक मिसाल कायम करने का मौका गंवा दिया। दोनों पक्षों को आगे बढ़ने के लिए जिस चीज़ की सर्वाधिक ज़रूरत थी, उनमें से कुछ भी सामने नहीं रखा। वार्ताकार आगे की राह टटोलने की बजाय अपनी-अपनी स्थितियां न्यायोचित ठहराने तक सीमित रहे। वे विरोधी के रूप में मिले। चाहते तो 'प्रवाह के संरक्षक' के रूप में लौट सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब गौरव या ज़मीन के मुद्दे पर बातचीत हो, तो हम वहीं अटक जाते हैं। जब अस्तित्व की साझा जीवन-रेखाओं पर बात करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे।

क्षैतिज गुरुत्वाकर्षण : नया स्थिरांक- अब हम किसी के सिंहासन के आकार या सीमा बहुत दूर होने से अधिक प्रभावित नहीं। नया स्थिरांक है आपसी निर्भरता; अदृश्य खिंचाव, जो ऊर्जा मार्ग, डेटा नेटवर्क और वित्तीय प्रणालियों को एकीकृत कार्यशील हकीकत में बांधता है। लंबवत ऊंचाई के लिए जैसे गुरुत्वाकर्षण काम करता है, वही काम क्षैतिज दिशा में प्रवाह का है। यह आम सहमति का इंतज़ार नहीं करता, न ही किसी आचार-संहिता से चालित है;यह तो बाध्यकारी है। पारस्परिक निर्भरता को हम नहीं चुनते; बल्कि इसी संग जन्म लेते हैं। आधुनिक राष्ट्र के लिए प्रवाह को नकारना ऑक्सीजन को नकारने जैसा है।

प्रवाह का सिद्धांत: प्रकृति का प्रथम नियम- प्रवाह प्रकृति का प्रथम नियम है: निरंतरता से ही स्थिरता बनी रहती है; इसमें आया व्यवधान प्रणालियों को पुन: अराजकता की ओर धकेल देता है। अगले दशकों में जीवित रहने के दायित्व का तालमेल निर्भरता से बैठाना होगा। जरूरी प्रवाह रुके नहीं।

खुले मार्गों से साझा नियमों तक: समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने यह स्वीकार किया कि गहरे समुद्र जैसे कुछ क्षेत्र खुले रहने चाहिए। इस प्रावधान ने पहुंच संरक्षित रखी; लेकिन निरंतरता सुनिश्चित नहीं की। प्रवाह का नियम इसमें अनिवार्य सुधार होना चाहिए। तब यह पहुंच को दायित्व में बदल देगा: परस्पर जुड़ी दुनिया में, मार्ग न केवल खुले, बल्कि कार्यात्मक भी रहें। अहम मार्गों का प्रवाह रोकने से फायदा नहीं होता; यह तो प्रणालीगत जोखिम है। यदि यह सिद्धांत इस्लामाबाद में हुई चर्चा में रखा होता, तो वार्ता अपनी-अपनी स्थिति का बचाव करने से हटकर मार्गों पर स्थिति की ओर मुड़ जाती व मिसाल कायम होती- समझौते के लिए नहीं, निरंतरता के लिए।

साझापन में विस्तार : साझापन की जरूरतें बदल चुकी हैं। वे अब केवल महासागर व वायुमंडल तक सीमित नहीं ; उनमें अब ऊर्जा गलियारा, व्यापारिक जलमार्ग और इंटरनेट की फाइबर-ऑप्टिक शामिल हैं। ये संपत्तियां न होकर जीवित रखने योग्य जीवन-रेखाएं हैं। इन पर किसी का एकाधिकार नहीं हो; इनकी देखभाल हो। इनमें पड़े व्यवधान का असर वैश्विक स्तर पर होता है क्योंकि परस्पर निर्भरता एक योजना है, विकल्प नहीं। आवश्यकता संप्रभुता के समर्पण की नहीं बल्कि निरंतरता की रक्षा करने वाले मानदंडों का विस्तार करने की है। किसी संकरे अहम मार्ग का संरक्षक मात्र एक द्वारपाल न होकर वैश्विक नब्ज की धड़कन का संरक्षक बने।

जिम्मेदारी और परिणाम : परिणामहीन कानून मात्र एक सुझाव है। निवेश : चाहे मलक्का स्ट्रेट हो या वैश्विक डेटा नेटवर्क, इनका प्रवाह सुनिश्चित करने वालों को ठोस प्रतिफल मिले। स्थिरता बनाए रखना एक सेवा है; इसका महत्व समझा जाए। सुधार : सामरिक लाभ के लिए ये प्रवाह रोकने वालों के लिए स्वत: स्फूर्त सामूहिक परिणाम भुगतने का प्रावधान बनाया जाए। ये उपाय दंडात्मक न होकर, सुधारात्मक होंगे। उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि प्रवाह बहाल रखना है।

संघर्ष से निरंतरता की ओर : यह आदर्शवाद नहीं, अपने सबसे अनुशासित रूप में यथार्थवाद है। प्रवाह का नियम टकराव खत्म नहीं करता; उसका दायरा सीमित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिद्वंद्विता मानव अस्तित्व की प्रणालियों को बंधक न बना पाए। स्थिरता निरंतरता की उपस्थिति है, न कि संघर्ष का अभाव। विश्व के संकरे मार्गों में, होर्मुज़ हो ,स्वेज हो या क्लाउड डाटा, वहां बनी निरंतरता जो स्थिरता दे सकती है, वह सियासी रूप से संभव नहीं। साझा निर्भरता से बंधे राज्य मानदंड तय कर सकते हैं और बोझ बांट सकते हैं, उपयोगिता के जरिये व्यवस्था बने, एक केंद्रीय प्रबंधन बनने की प्रतीक्षा न करें।

लापता कड़ी : प्रवाह के संरक्षक : संरक्षकों के बिना कोई सिद्धांत टिक नहीं सकता। मलक्का जलडमरूमध्य से लेकर होर्मुज़ और स्वेज तक, और आगे डिजिटल युग के अदृश्य द्वारों तक, निरंतरता के मार्ग अपने स्वाभाविक संरक्षकों को प्रकट कर चुके हैं। अस्पष्ट संघर्ष के इस युग में, व्यवधान शायद ही कभी स्वयं को घोषित करे। जलडमरूमध्य से आवाजाही पूरी थमने की बजाय धीमी हो जाती है। नेटवर्क रुकता नहीं, क्षीण होता है। दोषारोपण में देरी होती है और जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। फिर भी प्रभाव वही होता है: लड़खड़ाया प्रवाह, और साथ ही स्थिरता भी।

इसलिए, प्रवाह के नियम को इसे लागू करवाने वालों की एक नई श्रेणी हो : निरंतरता के संरक्षक। ये पारंपरिक अर्थों में गठबंधन नहीं , न ही दबाव बनाने के औजार। ये तो पूर्व-निर्धारित जिम्मेवार राष्ट्र अथवा उनका गठबंधन है, जिन्हें समुद्री अवरोध बिंदुओं, ऊर्जा गलियारों या डिजिटल नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रवाहों की तत्काल बहाली का कार्य सौंपा गया हो। उनका जनादेश सीमित है; उनकी वैधता शक्ति से चालित न होकर कार्य से प्राप्त होती है। इसे संभव बनाने के लिए, प्रवाह को वैश्विक सेवा के रूप में मान्यता मिले। इसे सुरक्षित रखने वालों को मुआवजा दिया जाए। बाधित करने वालों के लिए स्वचालित, सामूहिक प्रतिक्रिया तंत्र स्वत: सक्रिय हो जाए, जो त्वरित हो, नियमाधारित एवं सियासी विलंबों से मुक्त हो। इस ढांचे से संप्रभुता कम नहीं होगी। यह परस्पर निर्भरता से अनुशासित होगी। प्रवाह टूट जाने पर, आम सहमति की प्रतीक्षा न की जाए। इसे योजनाबद्ध ढंग से बहाल किया जाए

निष्कर्ष : गतिरोध का खतरा – इतिहास ने मार्ग खोले हैं। कानून ने उन्हें संरचना दी। वर्तमान समय की मांग है उनकी निरंतरता बनाए रखना। प्रवाह का सिद्धांत सियासी गतिरोध से परे है। यह भौतिकी जैसी सटीकता से कार्य करता है। हम संप्रभुता को अलगाव समझने की गलती करते हैं। यदि उत्तरदायित्व की अनुरूपता निर्भरता के अनुसार नहीं तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। इस सदी में, शक्ति का मापन इससे नहीं होगा कि राष्ट्र क्या नियंत्रित करने की ताकत रखते हैं, बल्कि इससे होगा कि किसका प्रवाह सुचारु है। जो प्रवाह बना रहना अनिवार्य है, थमने न पाए।

लेखक सेना की पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर एवं पुणे इंटरनेशनल सेंटर के संस्थापक ट्रस्टी हैं।

लोगों का जीवन सुधारने के लिए अमीर बनने का इंतजार जरूरी नहीं

ज्यां द्रेज

कई वर्षों बाद पिछले महीने केरल जाना मेरे लिए सुखद अनुभव रहा। 1980 के दशक में जब मैं पीएचडी कर रहा था तो केरल अपने बेहतरीन सामाजिक संकेतकों के लिए जाना जाने लगा था। मसलन, 1981 की जनगणना के समय केरल में 71त्न वयस्क महिलाएं साक्षर थीं, जबकि पूरे भारत में सिर्फ26% थीं। शिशु मृत्यु दर 1,000 जन्मों पर 37 थी, जबकि भारत में यह 110 थी। ये उपलब्धियां तब थीं, जब केरल देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक था।

इससे पता चलता है कि गरीब देशों को लोगों का जीवन सुधारने के लिए अमीर बनने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। विकास के शुरुआती दौर में भी सरकार और समाज ऐसे कदम उठा सकते हैं, जिनसे हर व्यक्ति की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। सभी को अच्छी शिक्षा देना इसका उदाहरण है, जो 'केरल मॉडल' का आधार है। याद रखें, पुराने दिनों में केरल का सामाजिक ढांचा बेहद दमनकारी था। जब स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के अंत में केरल गए तो जाति-भेद की कठोरता देखकर विचलित हुए थे। वंचित जातियों को शिक्षा के अधिकार के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है

1980 के दशक में जब केरल दुनिया में चर्चित होने लगा, तब कुछ विद्वानों ने चेतावनी दी कि केरल मॉडल टिकाऊ नहीं है। आर्थिक निवेश के बजाय सामाजिक विकास को प्राथमिकता देने की केरल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इन भविष्यवाणियों के विपरीत, केरल में सामाजिक संकेतक बेहतर होते रहे और लोगों की आय भी तेजी से बढ़ी। इसका कारण था कि राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी थी और बहुत से केरलवासी दुबई, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में काम करने लगे। राज्य के अंदर और बाहर, दोनों ही जगह केरल ने अपने मानव संसाधन विकास का फायदा उठाया।

कई मायनों में आज केरल का जीवन-स्तर तथाकथित विकसित देशों के बराबर है। उदाहरण के लिए, शिशु मृत्यु दर अब 1,000 जीवित जन्मों पर सिर्फ 5 है, जो अमेरिका से थोड़ी ही कम है। पूरे भारत में यह लगभग 25 है। इसी तरह, केरल में अधिकतर बच्चों को तीन साल की उम्र से ही प्री-स्कूल शिक्षा मिल जाती है, जबकि अमेरिका में यह सुविधा मुश्किल से आधे बच्चों को मिलती है।

केरल कई क्षेत्रों में देश से भी आगे निकल गया है। देश की सबसे मजबूत और सक्रिय ग्राम पंचायत, स्वयं-सहायता समूह और सहकारी संस्थाएं केरल में हैं। इनमें यूएलसीएसएस नामक एक सहकारी निर्माण कंपनी भी शामिल है, जहां 18,000 मजदूर बिना किसी मालिक के काम करते हैं। केरल में प्रवासी मजदूरों और निराश्रित परिवारों के लिए प्रगतिशील नीतियां भी हैं। 2018 की भयानक बाढ़ और कोविड संकट में भी केरल ने सामाजिक एकजुटता की मिसाल पेश की थी।

पिछले महीने केरल जाने पर मैंने एक और गुण देखा- जिम्मेदार नागरिकता की भावना। सुविधाघरों समेत सार्वजनिक जगहें बहुत साफ-सुथरी थीं। गाड़ियां जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकती हैं। लोग लाइन में खड़े होते हैं। कूड़ेदान का सही उपयोग होता है। और यह सब बिना किसी जोर-जबरदस्ती के होता है, क्योंकि समाज में सार्वजनिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो चुकी है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि केरल हर तरह से आदर्श है। वहां भी कई समस्याएं हैं, जैसे आत्महत्या की ऊंची दर और शिक्षित बेरोजगारी। लेकिन जब भारत 2047 तक विकसित बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसे केरल से सीख लेनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पर्यावरण के लिए गंभीर चेतावनी बनता डिजिटल प्रदूषण

डॉ. सुधिर कुमार

डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'अभौतिक' है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशत: जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है।

जब हम 'प्रदूषण' शब्द सुनते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में जहरीला धुआं उगलती चिमनियां, प्लास्टिक से पटी नदियां या सड़कों पर लगा कचरे का ढेर उभरता है। ये प्रदूषण के वे रूप हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ एक ऐसा अदृश्य जहर हमारे वातावरण और जीवन में घुल चुका है, जिसे हम देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन वह धीरे-धीरे हमारे पर्यावरण और मानसिक स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। इसे हम 'डिजिटल प्रदूषण' कहते हैं। भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी चरम पर है और 'डिजिटल इंडिया' का सपना साकार हो रहा है, इस अदृश्य खतरे पर कानून, नीति और जनजागरूकता के नजरिये से चर्चा करना अनिवार्य हो गया है।

लोग डिजिटल प्रदूषण को केवल 'ई-वेस्ट' यानी पुराने मोबाइल, टूटे लैपटॉप या खराब चार्जर तक सीमित मान लेते हैं। बेशक, ई-कचरा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन डिजिटल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा 'अभौतिक' है। इंटरनेट पर हमारा हर क्लिक, सर्च और क्लाउड स्टोरेज बिजली की भारी खपत करता है, जो अधिकांशत: जीवाश्म ईंधन से आती है और कार्बन उत्सर्जन बढ़ाती है। जब हम डेटा इस्तेमाल करते हैं, तो हजारों मील दूर स्थित विशाल डेटा सेंटर्स सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें चलाने और ठंडा रखने के लिए अत्यधिक ऊर्जा और पानी की आवश्यकता होती है। अत:, डिजिटल गतिविधियों का सीधा और गहरा प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है।

डिजिटल प्रदूषण के दो सबसे घातक पहलू 'डार्क डेटा' और 'डिजिटल फुटप्रिंट' हैं। 'डार्क डेटा' वह अनुपयोगी डेटा है जो कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा केवल स्टोर किया जाता है, जिसका दुनिया भर के कॉर्पोरेट डेटा में हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है। यह डेटा केंद्रों में व्यर्थ ऊर्जा की खपत करता है। वहीं, हमारा 'डिजिटल फुटप्रिंट' भी उतना ही खतरनाक है; एक स्पैम ईमेल अपने पूरे

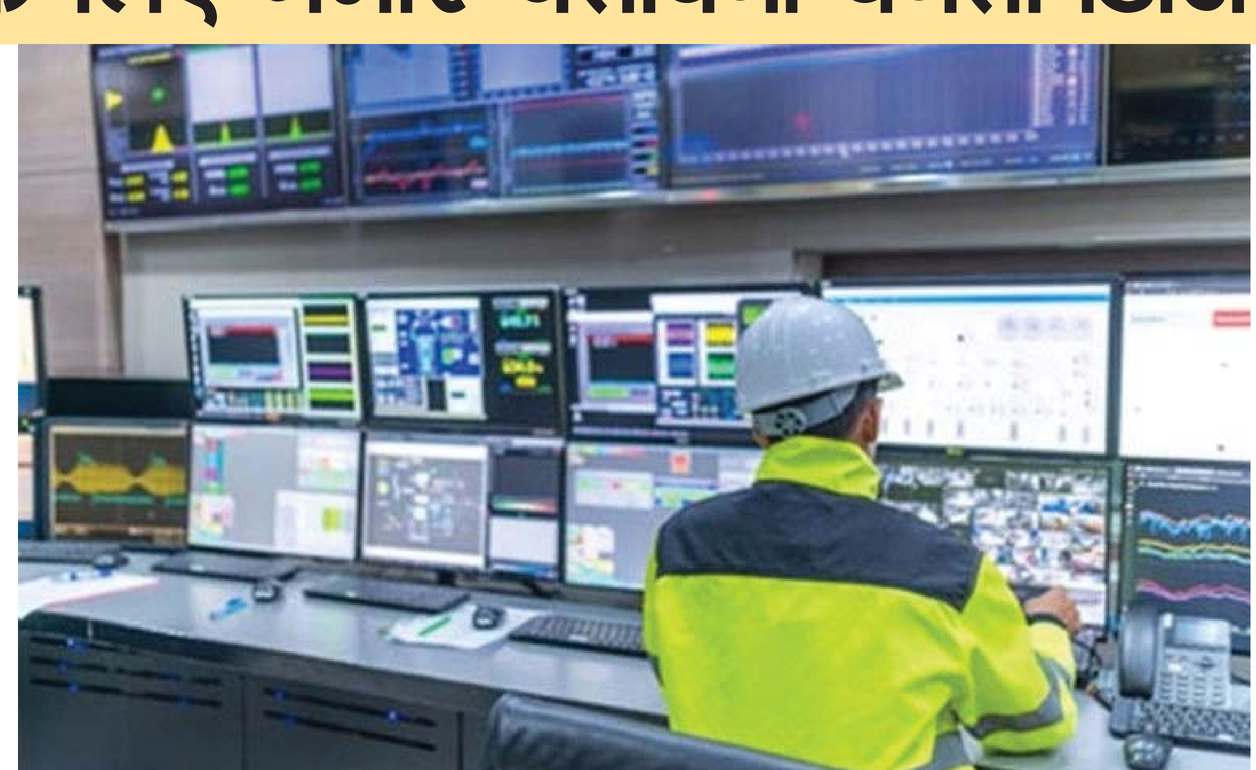

जीवनचक्र में लगभग 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने का जिम्मेदार है। यदि हम दुनियाभर में प्रतिदिन भेजे जाने वाले अरबों स्पैम और अनावश्यक ईमेल की गणना करें, तो यह प्रदूषण का स्तर वैश्विक विमानन उद्योग द्वारा फैलाए जाने वाले कुल उत्सर्जन के बराबर पहुंच जाता है। यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी एक छोटी-सी डिजिटल लापरवाही धरती के तापमान को बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है।

भारत में 'डिजिटल प्रदूषण' को सीधे तौर पर परिभाषित करने वाला कोई विशिष्ट या एकल कानून मौजूद नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986) और समय-समय पर संशोधित ई-कचरा प्रबंधन नियम (2016/2022) इसके केवल भौतिक हिस्से (हार्डवेयर कचरे) को कवर करते हैं। असली चुनौती डेटा केंद्रों से होने वाले ऊर्जा उत्सर्जन और 'डिजिटल हाइजीन' की है, जिसके लिए वर्तमान में स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों की कमी खलती है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार 'स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार' को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया है। यद्यपि ये मामले पारंपरिक औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित थे, लेकिन इनमें स्थापित 'प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा' और 'एहतियाती सिद्धांत' का दर्शन डिजिटल दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। जो कंपनियां विशाल डेटा सेंटर चलाती हैं और करोड़ों भारतीयों का डेटा प्रोसेस करती हैं, वे डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकतीं।

'भारत सरकार द्वारा 'राइट टू रिपेयर' पोर्टल का शुभारंभ एक क्रांतिकारी पहल है। कानूनी और नीतिगत रूप से यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है कि वे अपने गैजेट्स को कंपनियों के एकाधिकार से बाहर निकलकर ठीक करा सकें। यह पहल न केवल कंपनियों की 'प्लांड ऑब्सेसलेंस' (गैजेट्स को जानबूझकर ऐसा बनाना कि वे जल्दी खराब हो जाएं) की नीति पर लगाम लगाएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करने में भी मील का पत्थर साबित होगी। जब कोई उपकरण लंबा चलेगा, तो उसके निर्माण में लगने वाली ऊर्जा और उसके कचरे से होने वाले प्रदूषण में स्वत: कमी आएगी।'

केवल कानून और अदालती आदेश डिजिटल प्रदूषण का पूर्ण समाधान नहीं हैं; इसके लिए 'डिजिटल स्वच्छता' को जीवनशैली बनाना अनिवार्य है। शुरुआत इनबॉक्स की सफाई, अनावश्यक न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब करने और क्लाउड स्टोरेज से धुंधली तस्वीरों व पुराने बैकअप को हटाकर की जा सकती है। इसके साथ ही, वीडियो स्ट्रीमिंग के दौरान 'अति-उच्च परिभाषा' के बजाय सामान्य स्पष्टता का चुनाव करना डेटा केंद्रों पर दबाव और बिजली की खपत को कम करता है। यह 'डिजिटल क्लीन-अप' न केवल डेटा व्यवस्थित करता है, बल्कि ऊर्जा की बचत कर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अब सरकार को 'ग्रीन डेटा कानूनों' के माध्यम से टेक कंपनियों को अक्षय ऊर्जा (सौर, पवन) अपनाने और डेटा केंद्रों की ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए जवाबदेह बनाना होगा। हमें समझना होगा कि डेटा भले ही आभासी हो, पर उसे चलाने वाली ऊर्जा भौतिक है, जो धरती को प्रभावित करती है। आज समय की मांग है कि हम 'डिजिटल डिटॉक्स' के साथ-साथ 'डिजिटल क्लीन-अप' को अपनाएं।

लेखक कुरुक्षेत्र विवि. के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
www.onlytds.com
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544

श्रीकंचनपथ
छत्तीसगढ़

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करें
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

तालाबों को सूखने से बचाने पानी भरा जा रहा है

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 25 तालाबों की नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जल स्त्रोत स्वच्छ एवं उपयोगी बने रहें। आयुक्त राजीव पाण्डेय ने जोन आयुक्तों को निर्देशित किये हैं, कि तालाबों की नियमित सफाई कराई जावे। जिससे तालाबों के साथ क्षेत्र के गिरते जल स्तर को बचाया जा सके। भीषण गर्मी के चलते कई तालाबों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों के माध्यम से पानी छोड़ा गया है। यह पानी छोटे-बड़े नहरों से होते हुए तालाबों तक पहुंच रहा है, जिससे तालाबों का जल स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

जनगणना हेतु भिलाई में जन जागरूकता अभियान

भिलाई। जनगणना 2027 के अंतर्गत घर-घर जाकर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जनगणना के महत्व एवं सर्वेक्षण में सहयोग के लिए प्रेरित करने हेतु मुनादी कराई जा रही है। इस कार्य के लिए निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो क्षेत्रवार निगरानी करते हुए जनगणना कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वेक्षण कार्य पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

भिलाई में नाला, सब्जी मंडी और खेल परिसर का निरीक्षण

भिलाई। संभाग आयुक्त सत्य नारायण राठौर, कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-1 नेहरू नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुव्यवस्थित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान कोसा नाला, राधिका नगर रिक्त भूखण्ड, सब्जी मंडी एवं खेल परिसर का बारीकी से अवलोकन किया गया। राधिका नगर स्थित कोसा नाला में रिटर्निंग वाल निर्माण का संयुक्त निरीक्षण किया। नाले में बहते पानी के साथ जलकुंभी पाए जाने पर बरसात से पूर्व इसकी सफाई कराने के निर्देश दिए, ताकि वर्षा के समय जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। आकाश गंगा सब्जी मंडी में बढ़ती भीड़ और पार्किंग समस्या को देखते हुए सुपेला थाना के पीछे स्थित रिक्त भूमि का भी अवलोकन किया गया। यातायात व्यवस्था को सुचारू तरीके से बनाए रखने के लिए सब्जी मंडी को उक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। सब्जी मंडी निरीक्षण के दौरान व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी गईं।

माइन्स सेफ्टी फोर्टनाइट सेलिब्रेशन : सेल के राजहरा माइन्स को ओवरऑल प्रथम पुरस्कार

■ छत्तीसगढ़ की सभी सेल माइन्स ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। खदान सुरक्षा पखवाड़ा उत्सव (एएमएसएफसी-2025) का भव्य समापन अंबुजा सीमेंट प्लांट, रावन में आयोजित अंतिम समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप महानिदेशक खान सुरक्षा (डीजीएमएस), पश्चिम क्षेत्र, नागपुर के रामावतार मीणा द्वारा की गई।

इस अवसर पर खान सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, खान स्वामी एवं विभिन्न खदानों के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसने खनन क्षेत्र में सुरक्षा के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ रूप से प्रदर्शित किया।

एएमएसएफसी-2025 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्थित सेल की कुल नौ खदानों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज कराते हुए विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में राजहरा मेकनाइज्ड माइन्स एवं दल्ली मेकनाइज्ड माइन्स ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5-5 पुरस्कारों के साथ 2-2 फर्स्ट एड प्रतियोगिता पुरस्कार अर्जित किए। इसके अतिरिक्त झरनदल्ली मेकनाइज्ड माइन्स ने 3 पुरस्कार, महामाया माइन्स ने 4 पुरस्कार तथा डुलकी माइन्स ने 3 पुरस्कार प्राप्त किए।

वहीं कलवर आयरन ओर माइन्स, रावघाट आयरन ओर माइन्स, नंदिनी माइन्स एवं हिर्री डोलोमाइट माइन्स ने भी 1-1 पुरस्कार अर्जित कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।

समग्र प्रदर्शन के आधार पर राजहरा मेकनाइज्ड माइन्स को ओवरऑल प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया एवं महामाया माइन्स को ओवरऑल द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

यह उपलब्धि सेल खदानों में विकसित सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति, अनुशासित कार्यप्रणाली एवं सतत सुधार के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है। एएमएसएफसी-2025 द्वारा नियमित प्रशिक्षण, व्यापक जागरूकता एवं सुरक्षा के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण ही सुरक्षित एवं सतत खनन संचालन की आधारशिला होने का संदेश दिया गया।

दुर्ग निगम क्षेत्र में 18 स्थानों पर संचालित हैं वाटर एटीएम

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम दुर्ग द्वारा शहर के 18 प्रमुख स्थानों पर वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं, जिससे आम नागरिकों को किफायती दर पर शुद्ध पानी मिल रहा है।

इनमें से अधिकांश वाटर एटीएम सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। शेष 4 स्थानों मालवीय नगर, महिला समृद्धि बाजार सिकोला, सिकोला मार्केट एवं नया सब्जी मंडी सिकोला पर तकनीकी, वाटर लेवल डाउन एवं निर्माण संबंधी कारणों से अस्थायी रूप से संचालन प्रभावित हुआ है, जिनका शीघ्र निराकरण कर जन सुविधा को ध्यान रखकर वाटर एटीएम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध किया जा रहा है।

मालवीय नगर में पार्षद की अनुशंसा के अनुसार स्थल परिवर्तन के पश्चात कार्य से प्रगति पर है। वहीं महिला समृद्धि बाजार में शेड निर्माण कार्य जारी होने से पेयजल पाइप लाइन छत्तिग्रस्त

हुआ, पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जल आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसे विभाग द्वारा दुरुस्त कर शीघ्र चालू करने की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार नया सब्जी मंडी सिकोला में पंप एवं केबल की चोरी तथा बोरवेल के जलस्तर में कमी के कारण एटीएम बंद हुआ था। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्यवाही करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि जल्द ही आम जनता को पुन: सुविधा मिल सके।

नगर निगम दुर्ग द्वारा सभी बंद वाटर एटीएम को शीघ्र चालू किया जा रहा है,जिससे भीषण गर्मी में शहर के प्रत्येक नागरिक को निर्बाध रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके।

बीएसपी में पीएम-एनएपीएस के अंतर्गत 150 अप्रेंटिस का इंडक्शन

भिलाई। सेल- भिलाई इस्पात संयंत्र में कौशल विकास एवं युवा सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) के अंतर्गत 150 नए अप्रेंटिस का इंडक्शन किया गया। यह पहल 'स्किल इंडिया' मिशन को गति प्रदान करने की दिशा में संयंत्र का एक महत्वपूर्ण कदम है।

इन अप्रेंटिस को कोपा, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर एवं रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग (आरएसी) जैसे विभिन्न ट्रेड्स में संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुभवी मार्गदर्शकों एवं विशेषज्ञों के निर्देशन में संचालित होगा, जिससे प्रतिभागियों को व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव प्राप्त होगा तथा शैक्षणिक ज्ञान एवं वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को प्रभावी रूप से कम किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में व्यवहारिक अनुभव के साथ-साथ संरचित शिक्षण मॉड्यूल का समावेश हो, जिससे अप्रेंटिस तकनीकी दक्षता के साथ-साथ औद्योगिक प्रक्रियाओं की समग्र समझ विकसित कर सकें। इसके अंतर्गत प्रतिभागियों को आधुनिक उपकरणों, सुरक्षा मानकों एवं संयंत्र की वास्तविक कार्यप्रणालियों से भी परिचित कराया जाएगा।

नवीन संगीत महाविद्यालय के राजेन्द्र ने थाईलैंड में दी भावपूर्ण प्रस्तुति

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्ग के भरतनाट्यम विभाग अतिथि प्राध्यापक राजेंद्र कुमार ने थाईलैंड देश में जाकर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रस्तुति देकर हजारों लोगों का दिल जीत लिया और अपनी कला का खूबसूरत प्रदर्शन करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

उन्होंने साथी कलाकारों के साथ 30 मार्च सोमवार से 11 अप्रैल शनिवार तक थाईलैंड देश के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शानदार प्रस्तुति देकर पूरे भारत देश व छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रौशन किया है जो बहुत ही गर्व की बात है।

यह संगीत महाविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से सम्बद्ध है वहां के छात्र रहे होनहार कलाकारों राजेंद्र कुमार मो. आसिफ हुसैन, तोषिता असाटी, मधुश्मिता पॉल और एक्कलक नू नगियोन ने

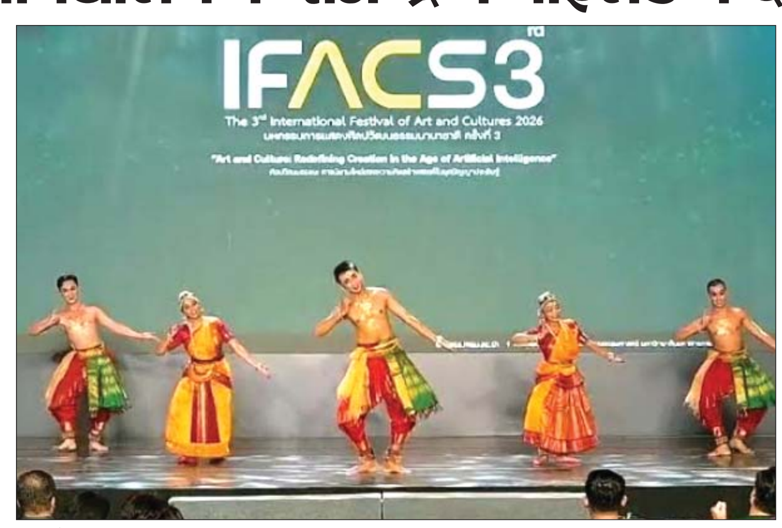

थाईलैंड में महासाराखाम विश्वविद्यालय के ललित अनुप्रयुक्त कला एवं संस्कृति विज्ञान संकाय द्वारा आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति सतत विकास सम्मेलन (आईसीएसएसडीफोर) व तीसरे अंतरराष्ट्रीय नृत्य महोत्सव में भाग लिया और अपनी खूबसूरत कला का शानदार प्रदर्शन किया। इस बड़ी उपलब्धि पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. ऋचा ठाकुर ने भी उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि कलाओं के लिये पूरी तरह समर्पित इस महाविद्यालय के लिए भी एक महत्वपूर्ण और बड़ी उपलब्धि है.

राजेंद्र कुमार ने बताया कि एक वर्ष पूर्व भी उन्होंने विदेश में ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रस्तुति दी थी और अब पुन: ये सुनहरा अवसर उन्हें इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मिला है जो कि बहुत ही खुशी की बात है।

उन्होंने भरतनाट्यम के कीर्तनम् एवं तिल्लाना की भाव सुर और ताल के साथ सुन्दर प्रस्तुति दी। सम्मेलन की थीम कला एवं संस्कृति : कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग मे सृजन की पुनरपरिभाषा पर राजेन्द्र कुमार ने शोध पत्र वाचन भी कियाजिसे अन्तराष्ट्रीय मंच पर अत्यंत सराहा गया। कार्यालय प्रमुख यशवंत साहू एवं महाविद्यालय परिवार ने उन्हें इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दीं।

आस्था वृद्धाश्रम के 9 बुजुर्गों की एम्स में हुई सफल सर्जरी

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। आस्था वृद्ध आश्रम, सेक्टर-2, भिलाई नगर द्वारा बुजुर्गों की सेवा का अनुकरणीय कार्य लगातार जारी है। संस्था के प्रयासों से अब तक एम्स रायपुर में 9 वृद्धजनों के जटिल ऑपरेशन सफल हो चुके हैं।

संस्था के संचालक प्रकाश गेडाम ने बताया कि हाल ही में आश्रम की 82 वर्षीय एक माताजी, जो मोतियाबिंद, लकवा और कमर-पैर की हड्डी टूटने से पीड़ित थीं, उनका एम्स रायपुर में सफल ऑपरेशन हुआ। एक आंख का ऑपरेशन पहले सेक्टर-9 अस्पताल में कराया गया था।

एम्स के डॉ. अग्रवाल, विभागाध्यक्ष, डॉ. सकरकर एवं संपूर्ण डिपार्टमेंटल टीम के प्रयास से ऑपरेशन पूर्णत: सफल रहा। चिकित्सकों के अनुसार माताजी लगभग दो माह बाद चलने लगेंगी।

प्रकाश गेडाम के अनुरोध पर अखिर भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में अभी तक चार पुरुष और चार माताओं के ऑपरेशन सफल हो चुके हैं। ये सभी बुजुर्ग अब चलने-फिरने लगे हैं। लगभग 2 साल पहले ऑपरेशन कराने वाली दो माताओं का बाद में स्वाभाविक देहांत हो गया। इस प्रकार संस्था के माध्यम से कुल 9 वृद्धजनों को नया जीवन मिला।

गेडाम ने कहा, इन सभी सफल ऑपरेशनों के लिए हम एम्स रायपुर के सभी डॉक्टरों और स्टाफ का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। ईश्वर से कामना है कि वर्तमान में भर्ती माताजी भी शीघ्र पूर्ण स्वस्थ हों।

उल्लेखनीय है कि आस्था संस्था पिछले 20 वर्षों से वृद्धजनों की सेवा कर रही है। संस्था द्वारा लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों के रिसर्च हेतु देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करने का कार्य भी किया जा रहा है। गेडाम ने इस पुनीत कार्य में सहयोग करने वाले सभी दानदाताओं और शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त किया।

कोहका क्षेत्र को वैशाली नगर थाना क्षेत्र में शामिल करने एसएसपी को दिया ज्ञापन, दूरी का दिया हवाला

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। कोहका क्षेत्र वर्तमान में स्मृति नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत आता है, जो इस क्षेत्र से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं, वैशाली नगर थाना कोहका क्षेत्र से मात्र लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

ऐसी स्थिति में क्षेत्रवासियों को किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा आपातकालीन स्थिति में स्मृति नगर चौकी तक पहुंचने में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूरी अधिक होने के कारण समय की भी हानि होती है, जिससे जनसुविधा प्रभावित होती है।

शारदा गुप्ता ने मांग की है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए कोहका क्षेत्र को स्मृति नगर चौकी से स्थानांतरित कर निकटतम वैशाली नगर थाना में विलय कि जाय, ताकि आम नागरिकों को त्वरित एवं सुगम पुलिस सेवाएं प्राप्त हो सकें। जनहित संघर्ष समिति के संयोजक शारदा गुप्ता ने इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की। मांग करने वालों में प्रमुख रूप से निशु पांडे, कन्हैया सोनी, बृजमोहन उपाध्याय, बंटी नाहर, विनोद उपाध्याय, अखिलेश वर्मा, जेपी घनघोरकर, संतोष जयसवाल, गुरनाम सिंह, महेश वर्मा, ओमप्रकाश यादव, राजू, सुभाष शर्मा, रमेश देशमुख, नेहरू साहू, तुषार देवांगन, निर्मल भारती, छोटू पासवान, हरीशचंद्र भारती शक्ति सिंह, टिंकू संजय दुबे, संजय साहू, गिरीश दिलीप दामले, नरेश, संतोष सोनी, अनिल सिंह. पीसी प्रसाद, योगेश यदु, मुकेश, आदि शामिल हैं।

देहदान, नेत्रदान एवं त्वचादान के लिए जागरूकता कार्यशाला

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। ज्येष्ठ नागरिक मंच, नेहरू नगर द्वारा देहदान, नेत्रदान एवं त्वचादान के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु एक प्रेरणादायक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में अंगदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना एवं उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना था।

इस अवसर पर नवदृष्टि फाउंडेशन के कुलवंत भाटिया, राजेश पारख एवं हरमन दुलई ने उपस्थित जनों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कुलवंत भाटिया ने नेत्रदान की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित भ्रांतियों पर विस्तार से चर्चा की।

हरमन दुलई ने देहदान के महत्व को सरल एवं सहज भाषा में समझाया, वहीं राजेश पारख ने त्वचादान की आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक मंच के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता सहित एस एन मोदी, डीके रॉय, दीपशिखा प्रसाद, बीएस खनूजा, एचएस रेखी, आरआर गर्ग, आरआर

बाजपेई, सुनील सोनी, विजय क्षीरसागर सहित लगभग 200 सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और विशेषज्ञों से अपने प्रश्नों के समाधान प्राप्त किए।

इस अवसर पर अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने बताया कि वर्ष 1992 में उन्होंने अपने पिता के नेत्रदान करवाए थे। बाद में उन्होंने अपनी माता के नेत्रदान का प्रयास भी किया, किन्तु तकनीकी कारणों से यह संभव नहीं हो सका। उन्होंने नवदृष्टि फाउंडेशन से आग्रह किया कि ज्येष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों को देहदान, नेत्रदान एवं त्वचादान से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं एवं आवश्यक सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी जाए, ताकि भविष्य में अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें।

राजेश पारख ने कहा कि इस आयु वर्ग में भी अंगदान के प्रति जागरूकता एवं जिज्ञासा सराहनीय है। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी सीखने का अवसर मिलेगा और इस अभियान को नई गति प्राप्त होगी।

नवदृष्टि फाउंडेशन की ओर से अनिल बल्लेवार, कुलवंत भाटिया, राज आढ़तिया, प्रवीण तिवारी, मुकेश आढ़तिया, हरमन दुलई, रितेश जैन, राजेश पारख, जितेंद्र हासवानी, मंगल अग्रवाल, किरण भंडारी, उज्जवल पींचा, सत्येंद्र राजपूत, सुरेश जैन, पीयूष मालवीय, दीपक बंसल, विकास जायसवाल, मुकेश राठी, प्रभु दयाल उजाला, प्रमोद बाघ, सपन जैन, यतीन्द्र चावड़ा, जितेंद्र कारिया, बंसी अग्रवाल, अभिजीत पारख, मोहित अग्रवाल, चेतन जैन, दयाराम टांक, विनोद जैन एवं राकेश जैन ने ज्येष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

आयुक्त ने प्रगति नगर में चल रहे कार्यो का किया निरीक्षण

भिलाई। नगर पालिक निगम के आयुक्त राजीव पाण्डेय ने वार्ड 30 प्रगति नगर में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने जोन-3 क्षेत्र अंतर्गत नवनिर्मित सीमेंटीकरण सड़कों तथा सुलभ शौचालय का जायजा लेते हुए संबंधित अभियंताओं को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने जलेबी चौक से लिंक रोड के पास निर्मित सीमेंटीकरण सड़क का अवलोकन किया। यह सड़क नागरिकों को सुगम यातायात सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इसके साथ ही टाटा लाइन क्षेत्र में निर्माणाधीन सीसी रोड एवं सुलभ शौचालय का भी निरीक्षण किया गया। पुराना शौचालय जर्जर हो जाने के कारण उसे हटाकर नया निर्माण कराया जा रहा है।

Since 1972
CROWN-TV®
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय

प्रधानमंत्री के दृढ़इच्छाशक्ति और साहसिक निर्णय से पूरा होगा महिलाओं का सपना : मुख्यमंत्री साय

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पारित होना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में नारी का स्थान सर्वोच्च है। हम भगवान से पहले भगवती की पूजा करते हैं और ऐश्वर्य के लिए माता लक्ष्मी, बुद्धि के लिए सरस्वती और बल के लिए दुर्गा की आराधना की जाती हैं।

श्री साय ने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया।

उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महतारी वंदन योजना जैसी पहलों ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हम इस वर्ष को प्रदेश में 'महतारी गौरव वर्ष' के रूप में मना रहे हैं और महतारी वंदन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद समाप्त हुआ है और प्रदेश विकास के नए मार्ग पर अग्रसर है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को नया संबल मिलेगा। कार्यक्रम में "पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी—नए भारत की तैयारी" के संकल्प को दोहराया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में पहले से ही 14 लाख से अधिक महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो उनके बढ़ते आत्मविश्वास का प्रमाण है। उन्होंने इस दौरान पुष्प के साथ महिलाओं का अभिनंदन कर बधाई और शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं की इच्छाशक्ति और संकल्प उन्हें बड़े निर्णय लेने में सक्षम बना रहे हैं। महिलाओं को जिम्मेदारी मिले तो वे देश की तस्वीर बदल सकती हैं। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने बताया कि यह अधिनियम वर्ष 2029 तक लागू होगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। कार्यक्रम में सांसद रूपकुमारी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पद्मश्री ऊषा बारले, विधायक पुरंदर मिश्रा, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा, पद्मश्री ऊषा बारले, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नीता डोंगरे सहित अनेक जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

कटे होंठ से टूटी हिम्मत तक, एक ऑपरेशन और बदल गई जिंदगी

सुकमा की बेटी लावण्या को मिली नई मुस्कान, मुख्यमंत्री ने दिया आशीर्वाद

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। कहते हैं कि सही समय पर मिला इलाज किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सुकमा जिले की 13 वर्षीय बालिका टुंकी लावण्या की कहानी इसी बात का जीवंत उदाहरण है, जिसने कठिन परिस्थितियों और वर्षों की पीड़ा के बाद आखिरकार एक नई मुस्कान और नया आत्मविश्वास पाया है।

लावण्या, जो कन्या आश्रम, गोल्लापल्ली (पालाचेलमा) की निवासी है, जन्म से ही क्लैफ्ट लिप (कटे होंठ) जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही थी। यह बीमारी सिर्फ शारीरिक दर्द तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके बचपन पर सामाजिक झिझक और आत्मविश्वास की कमी का भी गहरा असर डाल रही थी। परिवार में जागरूकता की कमी और इलाज को लेकर भय के कारण लंबे समय तक उसका उपचार नहीं हो पाया। लेकिन किस्मत ने तब करवट ली जब लावण्या मेगा सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य शिविर में पहुंची। शिविर में कलेक्टर श्री अमित कुमार और एसपी श्री किरण चव्हाण से मिली। उन्होंने लावण्या को स्वास्थ्य शिविर में जांच कराके बेहतर इलाज का प्रबंध किया। शिविर में मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने न सिर्फ लावण्या की जांच की, बल्कि उसके परिवार को समझाकर इलाज के लिए तैयार किया। इसी शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाया गया। जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए लावण्या को कालाडा अस्पताल, रायपुर भेजा गया। इस दौरान आरबीएसके चिरायु टीम ने उसे सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई।

10 अप्रैल 2026: जब दर्द की जगह उम्मीद ने ले ली– सभी प्रक्रियाओं और समन्वय के बाद आखिरकार 10 अप्रैल 2026 को लावण्या का सफल ऑपरेशन किया गया। यह सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि उसके जीवन के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी थी। ऑपरेशन के बाद लावण्या के चेहरे पर लौटी मुस्कान को देखकर परिवार की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वर्षों का दर्द और ताने जैसे उसी दिन समाप्त हो गए।

मुख्यमंत्री ने की मुलाकात, दिया आशीर्वाद

इस कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब 13 अप्रैल 2026 को सुकमा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ने लावण्या से मुलाकात की। उन्होंने लावण्या के स्वास्थ्य की जानकारी ली, उसे फल भेंट किए और उसके उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया।

सरकारी योजनाओं की सफलता की मिसाल बनी लावण्या

आज लावण्या के चेहरे पर लौटी मुस्कान केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य विभाग का समर्पण और समय पर उपचार दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी चमत्कार कर सकते हैं। लावण्या अब न सिर्फ स्वस्थ है, बल्कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भी लौट आया है। उसकी मुस्कान आज पूरे सुकमा के लिए प्रेरणा बन चुकी है।

व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनाएं- केन्द्रीय मंत्री ओंराव

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा निभाई गई परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि का दृष्टिकोण केवल रोजगार सृजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य उद्यमिता को बढ़ावा देना और व्यक्तियों को रोजगार चाहने वाला बनने के बजाय रोजगार देने वाला बनने में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में के 10 अप्रैल 2026 को आयोजित 25 वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए ओराम ने इस निगम को जनजातीय उद्यमिता के लिए एक उत्प्रेरक बताया।

केंद्रीय जनजाति मंत्री जुएल ओराम द्वारा छत्तीसगढ़ से चयनित लाभार्थी जिला बेमेतरा से किशन ध्रुव ग्राम कुआं (किराना व्यवसाय) एवं धनराज ठाकुर ग्राम गातापार (फोटो स्टूडियो व्यवसाय) सहित छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के प्रतिनिधि प्रवीण कुमार लाटा का स्वागत किया और सावधि ऋण योजना के तहत व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करने में उनके प्रयासों की सराहना की।

मंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर देते हुए ओराव ने निगम के उस मुख्य उद्देश्य को रेखांकित किया जिसके तहत वह बिना किसी गारंटी के वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे जनजातीय लाभार्थियों तक इसकी पहुँच और अधिक व्यापक हो सके। मीडिया से बात करते हुए श्री ओराम ने कहा कि निगम ने लाभार्थियों को 16 लाख से अधिक ऋण वितरित किए हैं और अब तक कुल संवितरण (वितरित राशि) 4,000 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने नई दिल्ली के विश्व युवा केंद्र में अपना 25 वां स्थापना दिवस मनाया।

साय सरकार की पहल से सशक्त हुई महिलाएं

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास अब सार्थक परिणाम दे रहे हैं। इसका प्रेरक उदाहरण गौरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत लालपुर की हमेश्वरी राठौर हैं, जो आज लखपति दीदी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं।

एक सामान्य ग्रामीण महिला से आत्मनिर्भर उद्यमी बनने तक का उनका सफर संघर्ष, साहस और सफलता की मिसाल है। हमेश्वरी राठौर रिद्धी-सिद्धी स्वसहायता समूह से जुड़ीं, जहां उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आर्थिक सहयोग और प्रशिक्षण मिला। समूह के माध्यम से उन्होंने 5 लाख 50 हजार रुपये का ऋण प्राप्त किया, जो उनके जीवन में परिवर्तन का आधार बना। इस राशि का उपयोग उन्होंने कृषि और छोटे व्यवसाय को विकसित करने में किया। सब्जी उत्पादन को मुख्य आय का स्रोत बनाते हुए उन्होंने टमाटर, गोभी, अदरक, बरबट्टी और हल्दी जैसी फसलों की खेती शुरू की। साथ ही, उन्होंने सेंटरिंग प्लेट का कार्य भी शुरू किया, जिससे उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत बने।

शुरुआती दौर में मौसम की अनिश्चितता, बाजार की चुनौतियां और लागत जैसी कठिनाइयां सामने आईं, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं से मिले मार्गदर्शन और स्वसहायता समूह के सहयोग ने उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अपने परिश्रम और दृढ़ निश्चय के बल पर उन्होंने हर बाधा को पार किया। आज हमेश्वरी राठौर की वार्षिक आय लगभग डेढ़ से दो लाख रुपये तक पहुंच चुकी है, जिसने उन्हें लखपति दीदी बना दिया है। उनकी सफलता ने न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, बल्कि वे क्षेत्र की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई हैं। योजनाएं और स्वसहायता समूहों का सशक्त नेटवर्क ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।

अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना, 850 तीर्थ यात्रियों को मिला लाभ

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बिलासपुर संभाग के विभिन्न जिलों के श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई, जब 850 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिलासपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई।

इस यात्रा के दौरान यात्रियों को अयोध्या धाम के दर्शन के साथ-साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन का भी पुण्य अवसर प्राप्त होगा। इस विशेष ट्रेन को केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर राजेश चंद्रवंशी, मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनुराग सिंह, जिला पंचायत सीईओ बिलासपुर संदीप अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

ट्रेन के प्रस्थान के दौरान रेलवे स्टेशन पर उत्साहपूर्ण वातावरण देखने को मिला।

जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, रेलवे तथा आईआरसीटीसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तीर्थ यात्रियों का स्वागत-सत्कार किया। यात्रियों को यात्रा से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए उनके सुखद एवं सुरक्षित सफर के लिए शुभकामनाएं भी दी गईं।

यह विशेष तीर्थ यात्रा न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का अवसर है, बल्कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यात्रियों में इस यात्रा को लेकर विशेष उत्साह एवं श्रद्धा का माहौल देखने को मिला।

धमतरी में STREE परियोजना का शुभारंभ: 300 ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया रास्ता

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में धमतरी जिले में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। कलेक्टोरेट परिसर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) रायपुर, जिला प्रशासन धमतरी और बीआरपी शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बीच STREE (Skill Development through Technological Resources for Empowering Economic Growth of Women) परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

इस महत्वपूर्ण अवसर पर NIT रायपुर के निदेशक डॉ. एन. वी. रमणा राव, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य ने संयुक्त रूप से रूश्व पर हस्ताक्षर कर परियोजना का विधिवत शुभारंभ किया।कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित अनेक शिक्षाविद् एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 90 लाख रुपये की सहायता से संचालित होगी। 36 माह की अवधि में 300 ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।परियोजना के तहत महिलाओं को कोसा रेशम प्रसंस्करण, फाइबर निष्कर्षण, आधुनिक बुनाई, उत्पाद डिजाइन, उद्यमिता विकास एवं मार्केट लिंकेज जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेष रूप से आदिवासी एवं वंचित वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग और मूल्य संवर्धन संभव हो सके। ज्ञात हो कि धमतरी में हैंडलूम और कृषि आधारित आजीविका की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें इस परियोजना के माध्यम से तकनीकी सहयोग से सशक्त किया जाएगा। वहीं, हृद्धञ्ज रायपुर के निदेशक डॉ. रमणा राव ने इसे समावेशी नवाचार और जमीनी विकास की दिशा में एक मजबूत कदम बताते हुए महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने की बात कही। यह पहल न केवल महिलाओं को कौशल विकास का अवसर देगी, बल्कि उन्हें स्वरोजगार और लघु उद्योगों की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। स्ञ्जक्रक्ष्श्र परियोजना धमतरी में महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी मॉडल स्थापित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी।

रवीना टंडन की बेटी और राजकुमार हिरानी के बेटे की जोड़ी तैयार, मचेगा धमाल

बॉलीवुड में एक और धमाकेदार स्टार किड डेब्यू की तैयारी पूरी हो चुकी है। अभिनेत्री रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और मशहूर निर्देशक राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी अब एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं। वीर की सिनेमाघरों में आने वाली इस पहली फिल्म में राशा उनके साथ रोमांस करती दिखेंगी। फिल्म के लिए काफी समय से हीरोइन की तलाश चल रही थी, जो अब आखिरकार राशा पर आकर खत्म हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी को अपनी पहली थिएट्रिकल फिल्म के लिए लीड हीरोइन मिल गई है। जय शेवक्रमणि के अगले प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म में रवीना की बेटी राशा थडानी को उनके अपोजिट कास्ट किया गया है। इस फिल्म का नाम फिलहाल लगन लागी रे रखा गया है। कुल मिलाकर 2 बड़े फिल्मी घरानों के वारिसों को एक साथ देखना दर्शकों के लिए काफी रोमांचक होने वाला है।

ये फिल्म एक ताजा और युवाओं पर आधारित प्रेम कहानी बताई जा रही है, जिसका निर्देशन सोनाली रतन देशमुख करेंगी। सोनाली इससे पहले अपने पति कुणाल देशमुख के साथ जन्नत, तुम मिले और शिद्दत जैसी मशहूर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों में बतौर सहायक निर्देशक काम कर चुकी हैं।

निर्माता पर्दे पर एक बिल्कुल नई जोड़ी पेश करना चाहते थे और उनका मानना है कि वीर-राशा एक बेहद शानदार रोमांटिक जोड़ी साबित होंगे। इस फिल्म की शूटिंग जुलाई 2026 में शुरू होगी।

ये वीर हिरानी की बड़े पर्दे पर पहली फिल्म होगी। अभिनय की दुनिया में ये उनका दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले वो जियो हॉटस्टार की आने वाली सीरीज प्रीतम पेड्रो में नजर आएंगे, जो एक साइबर क्राइम थ्रिलर सीरीज है। इस सीरीज को उनके पिता ने बनाया है।

उनके साथ अरशद वारसी और विक्रांत मैसी जैसे कलाकार हैं। लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से स्नातक वीर पहले ही थिएटर जगत में अपनी पहचान बना चुके हैं।

जहां तक राशा की बात है, उन्होंने पिछले साल अभिषेक कपूर की पीरियड ड्रामा फिल्म आजाद से अभिनय की शुरुआत की थी। हालांकि, उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही।

उधर राशा भी अपने अभिनय से दर्शकों को कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाईं। वो बात अलग है कि इस फिल्म के पार्टी नंबर उई अम्माज ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब मशहूर कर दिया था। राशा अभिनेता अभय वर्मा के साथ लइकी लइका भी लेकर आ रही हैं।

नेहा धूपिया की हॉलीवुड में दस्तक

फिल्म 52 ब्लू से सामने आई पहली झलक

अभिनेत्री नेहा धूपिया अपनी अपकमिंग फिल्म 52 ब्लू को लेकर चर्चा में हैं। इस फिल्म से वह हॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं। फिल्म के मेकर्स ने इसका पहला लुक और ट्रेलर जारी किया है। नेहा धूपिया इसमें एक अलग लुक में नजर आ रही हैं। यह फिल्म फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बैकग्राउंड में एक भारतीय प्रवासी मजदूर की जिंदगी पर आधारित है।

2 मिनट 11 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नेहा धूपिया ने उस व्यक्ति (यादव शशिधर) की मां का किरदार निभाया है, जो लियोनेल मेस्सी का बहुत बड़ा फैन है। वो लियोनेल मेस्सी से मिलने विदेश जाता है। वहां जाकर वह फंस जाता हैं। भारत में आशीष का परिवार पहले तो उनके विदेश जाने पर खुश होता है, बाद में जब वह वापस नहीं आता है, तो परिवार के लोग परेशान होते हैं। बेटे के दूर हो जाने पर नेहा धूपिया भी परेशान होती हैं।

इस फिल्म में नेहा धूपिया पहली बार एक मां का किरदार निभाएंगी। उनके साथ आदिल हुसैन भी हैं, जो उनके पति का किरदार निभा रहे हैं। यह इन दोनों की पहली ऑन-स्क्रीन जोड़ी है।

फिल्म का ज्यादातर हिस्सा कोच्चि में फिल्माया गया है, जहां के तटीय और द्वीपीय नजारे कहानी को बेहतर तरीके से पेश करते हैं। यह फिल्म मिस्र के फिल्ममेकर अली अल-अरबी के निर्देशन में बनी है। आपको बता दें कि नेहा धूपिया ने 2003 में फिल्म कयामत से बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

आखिरी बार वह फिल्म बैड न्यूज 2024 में नजर आई थीं। अब वह हॉलीवुड फिल्म 52 ब्लू में नजर आएंगी।

क्या महिलाओं को जिम में नहीं करनी चाहिए ये एक्सरसाइज?

महिलाओं के लिए जिम जाना या व्यायाम करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन कई बार हमें कुछ ऐसी गलत धारणाएं सुनने को मिलती हैं, जो हमारे मन में कई सवाल खड़े कर देती हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही गलत धारणाओं को दूर करेंगे, ताकि महिलाएं सही जानकारी के आधार पर अपनी फिटनेस यात्रा शुरू कर सकें।

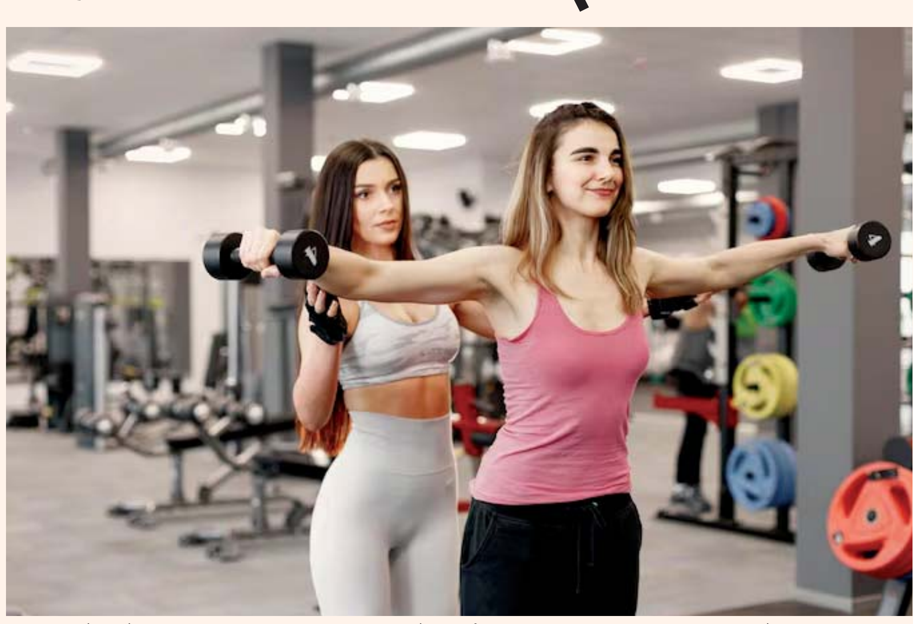

क्या भारी वजन उठाने से मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं?

एक आम धारणा यह है कि भारी वजन उठाने से महिलाओं की मांसपेशियां बहुत बड़ी हो जाती हैं। यह सच नहीं है। महिलाओं का शरीर पुरुषों की तरह मांसपेशियों को बढ़ाने वाले हार्मोन से संपन्न नहीं होता, जिससे उनकी मांसपेशियां बहुत बड़ी हो सकें। महिलाएं भारी वजन उठाकर अपनी मांसपेशियों को टोन कर सकती हैं, लेकिन वे इतनी आसानी से बड़ी नहीं होंगी। इसलिए महिलाएं बिना किसी डर के भारी वजन उठा सकती हैं।

क्या कार्डियो ही सबसे अच्छा व्यायाम है?

कई लोग मानते हैं कि कार्डियो ही सबसे अच्छा व्यायाम है और इससे ही वजन कम होता है। हालांकि, यह सही है कि कार्डियो वजन घटाने में मदद करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्य व्यायाम अहम नहीं होते। वजन उठाना, योगा या पिलाटिस जैसी व्यायाम भी बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए कार्डियो के साथ-साथ मांसपेशियों की व्यायाम भी जरूरी है।

क्या महिलाएं स्क्वाट और डेडलिफ्ट जैसी व्यायाम न करें?

बहुत से लोग महिलाओं को स्क्वाट और डेडलिफ्ट जैसी व्यायाम करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे शरीर का आकार बिगड़ जाएगा या मांसपेशियां बहुत बड़ी हो जाएंगी। यह पूरी तरह गलत है। सही तरीके से की गई व्यायाम से न केवल मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि शरीर का संतुलन भी बेहतर होता है। इसके अलावा ये व्यायाम दिल की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होती हैं।

क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने पर वजन बढ़ जाता है?

कई लोग मानते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने पर वजन बढ़ जाता है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन बेहतर होता है। इससे वजन कम करने में मदद मिलती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि वे इन गलत धारणाओं से प्रभावित न हों और सही जानकारी के आधार पर अपनी फिटनेस यात्रा जारी रखें। इससे न केवल उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

मनोज बाजपेयी से टक्कर लेने के लिए विलेन बनेंगी दिव्या दत्ता

राणा दग्गुबाती संभालेंगे कमान

मनोज बाजपेयी को आखिरी बार फैमिली मैन सीजन 3 में देखा गया था। अब अभिनेता ने अपनी अगली फिल्म के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें उनके साथ दिव्या दत्ता भी नजर आएंगी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में अभिनेत्री बतौर खलनायिका शामिल होंगी और अभिनेता की मुश्किलें बढ़ाएंगी। यह फिल्म मशहूर लेखक अरविंद अडिगा के उपन्यास लास्ट मैन इन टावर पर आधारित होगी, जिसका ऐलान नवंबर, 2025 में किया गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के निर्देशन की कमान साउथ अभिनेता राणा दग्गुबाती ने उठाई है। सूत्र ने बताया कि दिव्या का किरदार केंद्रीय भूमिका निभाने वाला है। उन्होंने कहा, दिव्या की खलनायिका एकतरफा नहीं है; उसे निर्मम और चालाक दिखाया गया है, लेकिन उसमें कुछ कमजोरियां भी हैं। यह फिल्म दिव्या और मनोज के किरदारों के बीच तनाव पर आधारित है। परियोजना पर काम जारी है और निर्माताओं का लक्ष्य जुलाई से दिसंबर, 2026 के बीच शूटिंग शुरू करना है।

मुंबई की एक आवासीय कॉलोनी में घटित लास्ट मैन इन टावर की कहानी एक ऐसे शिक्षक के इर्द-गिर्द घूमेगी जो इमारत के पुनर्विकास पर विचार किए जाने के दौरान एक रियल एस्टेट डेवलपर को अपना फ्लैट बेचने से मना कर देता है। इस कहानी के जरिए लेखक ने अपने उपन्यास में लालच, महत्वाकांक्षा और शहरी विकास जैसे विषयों को उजागर किया है। बता दें, दिव्या को हाल ही में रिलीज चिरैया सीरीज के लिए काफी सराहना और तारीफें मिली हैं।

कानों से जुड़ी इन 5 गलत धारणाओं को सच मानते हैं लोग, जानिए सच्चाई

कान हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और इनकी देखभाल करना बहुत अहम है। हालांकि, कानों से जुड़ी कई गलत धारणाएं हैं, जिन्हें लोग सच मानकर अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लेते हैं। इन गलत धारणाओं में से कुछ तो इतनी आम हैं कि लोग इन्हें बार-बार सुनते हैं और बिना सोचे-समझे अपनाते भी हैं। आइए आज हम आपको कानों से जुड़ी ऐसी ही कुछ गलत धारणाओं और उनकी सच्चाई के बारे में बताते हैं।

क्या कानों में झांकना खतरनाक होता है?

कई लोगों का मानना है कि किसी के कान में झांकना खतरनाक हो सकता है। हालांकि, सच्चाई यह है कि अगर कान साफ हो और कान के पर्दे पर जोर से न झांका जाए तो कान में झांकने से कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा कानों में झांकने से कान की गहराई तक पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए कानों में झांकने से कोई नुकसान नहीं होता।

क्या कान में रूई लगाना जरूरी होता है?

अक्सर लोग यह मानते हैं कि कान में रूई लगाना जरूरी होता है, खासकर जब बारिश हो या तैराकी के बाद। हालांकि, ऐसा करना गलत है क्योंकि इससे कान में नमी फंस सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बेहतर होगा कि बारिश के बाद या तैराकी के बाद कान को अच्छे से पोंछ लें ताकि नमी न रहे और संक्रमण का खतरा भी कम हो जाए।

क्या कान में मोम होना बुरा संकेत है?

यह भी एक आम धारणा है कि कान में मोम होना बुरा संकेत है। असल में कान में मोम होना एक सामान्य प्रक्रिया है और यह कान को संक्रमण से बचाने में मदद करता है। अगर मोम बहुत अधिक हो या गाढ़ा हो तो डॉक्टर से जांच कराएं ताकि कोई समस्या न हो। अपने कान को साफ रखने के लिए कभी भी किसी भी तरह के घरेलू उपाय अपनाने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें।

क्या कान में दर्द होना हमेशा संक्रमण का संकेत होता है?

यह भी एक आम धारणा है कि कान में दर्द होना हमेशा संक्रमण का संकेत होता है। असल में कान में दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि दांतों की समस्या, साइनस संक्रमण या हवा के दबाव में बदलाव। इसलिए जब भी आपके कान में दर्द हो तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही कारण पता चल सके और उचित इलाज मिल सके। सही जानकारी और समय पर इलाज लेने से समस्या जल्दी ठीक हो सकती है।

क्या कान में हेयरपिन डालने से कान में मोम निकलता है?

यह भी एक आम धारणा है कि कान में हेयरपिन डालने से कान में मोम निकलता है। हालांकि, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है या कान की गहराई तक पहुंच कर चोट लग सकती है। इसलिए कभी भी इस तरह के घरेलू उपाय अपनाने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें और कान की सफाई के लिए सुरक्षित तरीके अपनाएं।

खास खबर

नेशनल लोक अदालत 9 मई को, अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रचार-प्रसार तेज

बेमेतरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत 09 मई 2026 के सफल आयोजन एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के उद्देश्य से व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन सरोज नंद दास, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के मार्गदर्शन में एवं स्वर्णप्रभा यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान जानकारी दी गई कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों जैसे बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, राजस्व प्रकरण, चेक बाउंस मामले, विद्युत एवं जल कर से संबंधित प्रकरणों सहित अन्य सिविल व आपराधिक मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों में पक्षकारों को न्यायालय शुल्क की वापसी की जाती है तथा निर्णय के विरुद्ध कोई अपील भी नहीं होती, जिससे समय एवं धन दोनों की बचत होती है। नि:शुल्क विधिक सहायता एवं सलाह हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के टोल फ्री नंबर 15100 तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा के दूरभाष नंबर 07824-299152 पर संपर्क किया जा सकता है।

चना, मसूर एवं सरसों विक्रय हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव द्वारा जिले में रबी मौसम की दलहन एवं तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पाद को प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने हेतु कृषि विभाग सहित संबंधित विभागों को किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने तथा समुचित व्यवस्था बनाकर खरीदी करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के पालन में जिले की 15 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों एवं एक एफपीओ स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड सुकुलदैहान द्वारा पीएम-आशा योजना अंतर्गत दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीदी की जा रही है। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में तथा दलहन एवं तिलहन क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) लागू की गई है। जिले में 15 उपार्जन केन्द्रों एवं एक एफपीओ को अधिसूचित किया गया है। राज्य शासन द्वारा नाफेड के माध्यम से खरीदी की जा रही है। निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार सोयाबीन 5328 रूपए प्रति क्विंटल, अरहर 8000 रूपए प्रति क्विंटल, चना 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रूपए प्रति क्विंटल एवं सरसों 6200 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में अब तक कुल 1451 क्विंटल फसलों की सफलतापूर्वक खरीदी की जा चुकी है।

सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होंगे नवगठित पैक्स : मुख्यमंत्री

- प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर हुई 2 हजार 573
- किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण की सुविधा

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का किया वर्चुअल शुभारंभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश की नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया।उन्होंने इसे प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि **सहकार से समृद्धि** के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई समितियों के शुरू होने से अब पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2 हजार 573 हो गई है। उन्होंने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक और सहकारिता के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रही है, ताकि गांव और किसान समृद्ध बन सकें। उन्होंने बताया कि अब पैक्स समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में कार्य करेंगी, जिससे किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध होंगी। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया भी आसान होगी और किसान अपनी नजदीकी समिति में ही धान बेच सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से कार्यरत 2058 समितियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कंप्यूटरीकृत किया गया है और इनमें माइक्रो एटीएम भी लगाए गए हैं, जिनसे किसान 20 हजार रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नवगठित 515 समितियों में से 197 समितियां आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, जिससे दूर-दराज के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये समितियां केवल खाद-बीज वितरण तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि भविष्य में दुग्ध उत्पादन, मछली पालन जैसे सहायक कृषि गतिविधियों से भी जुड़ेंगी। साथ ही समितियों में लोक सेवा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे, जहां एक ही स्थान पर 25 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इन समितियों के सदस्य बनकर इसका अधिकतम लाभ उठाएं और इनके संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री केदार कश्यप वर्चुअल उपस्थित रहे, साथ ही कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी केदारनाथ गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत तथा सचिव सहकारिता सी.आर. प्रसन्ना, सहकारिता विभाग के प्रबंध संचालक के.एन. कांडे सहित विभिन्न जिलों से लगभग 2500 जनप्रतिनिधिगण, किसान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

ई-ऑफिस से परिलक्षित हो रही है श्रेष्ठ कार्य संस्कृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचारियों को ई-ऑफिस पर श्रेष्ठ कार्य करने एवं बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए श्रेष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने कहा है कि मंत्रालय में सभी अधिकारी-कर्मचारी ई-ऑफिस पर बढ़-चढ़कर काम कर रहें हैं। इससे अच्छी कार्य संस्कृति परिलक्षित हो रही है, वहीं पर अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहें हैं। इससे मंत्रालय में समयबद्धता में सुधार आया है।

मुख्य सचिव ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से कहा है कि वे समय पर मंत्रालय में उपस्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे आगामी दिनों में शत् प्रतिशत समयबद्धता देखी जा सकेगी। मुख्य सचिव ने मंत्रालय में ई-फाईल सिस्टम के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण की आवश्यकता बतायी। अत: उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन कर्मचारियों-अधिकारियों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उन्हें एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय में विभिन्न श्रेणीयों में ई-ऑफिस, बायोमेट्रिक उपस्थिति और ई-फाईल प्रणाली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इसमें संयुक्त सचिव स्तर के आदिवासी विकास विभाग के प्रथम स्थान पर संयुक्त सचिव भूपेन्द्र कुमार राजपूत, दूसरे स्थान पर लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त सचिव सत्यनारायण वास्तव, तीसरे स्थान पर आदिम जाति विकास विभाग के संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेद्वी को सम्मानित किया गया। उप सचिव स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर जीएडी के किशोर कुमार भूआर्य, दूसरे स्थान पर वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के दुर्देशी राम सोनटापर, तीसरे स्थान पर गृह विभाग के कांत वर्मा को सम्मानित किया गया। अवर सचिव स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर जीएडी के कैलाश कुमार नेताम रहें। द्वितीय स्थान पर वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के एम.एल.पवार, तृतीय स्थान पर गृह विभाग के पूरन लाल साहू रहे। अनुभाग स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर जीएडी के नंदकुमार मेश्राम, दूसरे स्थान पर वित्त विभाग के आशीष कुमार शर्मा, तीसरे स्थान पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मणिराम रात्रे रहे। सहायक अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों में प्रथम स्थान पर मुख्यमंत्री सचिवालय के सूरज कुमार देवांगन रहे। वरिष्ठ सचिवालय सहायक स्तर पर प्रथम स्थान पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग श्यामलाल साहू और दूसरे स्थान पर महिला एवं बाल विकास विभाग के दौलत राम वर्मा रहे।

बायोमेट्रिक अटेंडेंश के लिए समयबद्धता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुभाग अधिकारी अशीष कुमार अग्रवाल, उप सचिव मती क्लेमेन्टीना लकड़ा, सहायक अनुभाग अधिकारी सु कांती सूर्यवंशी, कनिष्ठ सचिवालय सहायक मुकेश राम प्रधान, सहायक अनुभाग अधिकारी पवन कुमार साहू, अवर सचिव राजीव कुमार झाड़े, अनुभाग अधिकारी राजेश कुमार जैन, वरिष्ठ सचिवालय सहायक राजेश कुमार टोप्पो, सहायक अनुभाग अधिकारी शार्दूल पटेल, वरिष्ठ सचिवालय सहायक सूरज कुमार साहू, वरिष्ठ सचिवालय सहायक तारा कुजूर, सहायक अनुभाग अधिकारी विनोद कुमार अथंकर को मुख्य सचिव ने सम्मानित किया।

युवाओं के सर्वांगीण विकास का मंचः युवा उत्सव 2026 की तैयारियों पर मंथन

श्रीकंचनपथ न्यूज

धमतरी। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों एवं आईटीआई के प्राचार्यों, फेकल्टी तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति में आगामी 24-25 अप्रैल को आयोजित होने वाले युवा उत्सव 2026-इंटर कॉलेज प्रतियोगिता की तैयारियों की समीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बैठक ली। रूपरेखा, व्यवस्थाओं, सहभागिता एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि युवा उत्सव में 20 से अधिक विधाओं को शामिल किया गया है, जिनमें वाद-विवाद, फोटोग्राफी, एकल एवं समूह नृत्य, एकल एवं समूह गायन, म्यूजिकल बैंड, क्विज प्रतियोगिता तथा विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं प्रमुख हैं। इसके साथ ही प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लल्लनटॉप के सौरभ द्विवेदी का प्रेरक सत्र, बस्तर का लोकप्रिय वायरा बैंड एवं आवाज क्रांति बैंड की विशेष प्रस्तुतियां भी युवाओं को आकर्षित करेंगी। उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन को सुव्यवस्थित, आकर्षक एवं यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण की जाएं।

सड़क सुरक्षा के साथ शिक्षा की राह भी रोशन कर रहा एनएचएआई

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर और एनएचआईटी ने सामाजिक सरोकार की दिशा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तरपोंगी में विद्यार्थियों को निशुल्क पावर चश्मों का वितरण किया। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूर्व में विद्यालय परिसर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 517 विद्यार्थियों की आंखों का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण किया गया। इस जांच के दौरान जिन 42 बच्चों की दृष्टि कमजोर पाई गई थी, आज उन्हें उनकी आवश्यकता और निर्धारित पावर के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले चश्मे सौंपे गए।

एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार लाल ने कहा कि एनएचएआई का उद्देश्य केवल सड़कों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि उन सड़कों पर चलने वाली अगली पीढ़ी के भविष्य को भी सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे बेहतर विज़न के साथ जीवन के हर पथ पर सुरक्षित और निडर होकर आगे बढ़ें।

इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी सहित विद्यालय के शिक्षक और छात्र उपस्थित रहे।

नारी शक्ति वंदन पदयात्रा को जन-आंदोलन बनाएंगे, लोरमी में गूंजा महिला सशक्तिकरण का स्वर : रत्नावली कौशल

श्रीकंचनपथ न्यूज

मुंगेली। केंद्र सरकार की 'नारी शक्ति वंदन योजना' के अंतर्गत भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अंजना देवी दास के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन एवं सामाजिक-राजनीतिक सहभागिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज लोरमी नगर में भव्य 'नारी शक्ति वंदन पदयात्रा' का विशाल आयोजन किया गया। माता महामाया मंदिर के पावन प्रांगण से प्रारंभ होकर यह पदयात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ठाकुर देव मंदिर में पूर्ण गरिमा के साथ संपन्न हुई।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता एवं नारी शक्ति के प्रतीक स्वरूप दीप प्रज्ज्वलन तथा पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया।पदयात्रा के शुभारंभ अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व सदस्य रत्नावली कौशल ने उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा माता महामाया और ठाकुर देव के आशीर्वाद से आज हम नारी शक्ति वंदन पदयात्रा का शंखनाद कर रहे हैं।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' एक युगांतरकारी निर्णय है, जिसने भारत की बेटियों को केवल कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी से ऊपर उठाकर देश की नीति-निर्माता बनाने का ऐतिहासिक मार्ग प्रशस्त किया है।लोकसभा और विधानसभाओं में 33त्न आरक्षण के माध्यम से अब गाँव की बेटी भी दिल्ली में बैठकर अपने गाँव, प्रदेश और देश की तकदीर लिखेगी।

रत्नावली कौशल ने स्पष्ट किया कि यह पदयात्रा मात्र औपचारिक भ्रमण नहीं, अपितु सामाजिक चेतना का अभियान है। हमें घर-घर तक यह विश्वास पहुँचाना है कि बेटी अब बोझ नहीं, बल्कि राष्ट्र का भविष्य और परिवार का गौरव है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसान, श्रमिक एवं पिछड़े वर्ग की बहनों को शिक्षा, कौशल विकास, मुद्रा लोन, स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और डिजिटल साक्षरता से जोड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा लक्ष्य है।

रत्नावली कौशल ने बताया कि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष विभा अवस्थी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले, मंडल एवं शक्ति केंद्र तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रावधानों को लेकर जागरूकता अभियान, विधिक साक्षरता शिविर, कौशल प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार मेलों का सतत आयोजन किया जाएगा, ताकि प्रदेश की हर बेटी सम्मान, शिक्षा और समान अवसर के साथ राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन सके।

महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अंजना देवी दास ने भाजपा के समस्त जिला व मंडल पदाधिकारियों, मातृशक्ति, महिला मोर्चा एवं समस्त कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा, इस पदयात्रा को हमें जन-आंदोलन का स्वरूप देना है। जब तक समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ी महिला शिक्षित, सुरक्षित और स्वावलंबी नहीं होगी, तब तक 'विकसित भारत 2047' का संकल्प अधूरा रहेगा।

आइए, आज महामाया मंदिर से ठाकुर देव तक कदम से कदम मिलाकर चलें और यह प्रण लें कि प्रत्येक नारी का सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन सुनिश्चित करेंगे। पदयात्रा में सम्मिलित मातृशक्ति ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ से बेटी बढ़ाओ', 'नारी शक्ति जिंदाबाद', '33 प्रतिशत आरक्षण-महिला सम्मान' जैसे ओजस्वी नारों से अंकित तख्तियां थामकर जन-जागरण का प्रभावी संदेश दिया।

जशपुर में 82 हजार से अधिक हितग्राहियों तक पहुंच रही योजनाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जिले के हजारों जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। वृद्धजन, विधवा, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए संचालित इन योजनाओं से जिले में कुल 82 हजार 583 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, जो सामाजिक सुरक्षा के मजबूत तंत्र को दर्शाता है।

समाज कल्याण विभाग की योजनाएं न केवल आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं, बल्कि सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बना रही हैं। उप संचालक समाज कल्याण विभाग ने बताया कि विभाग की ये योजनाएं जशपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार कर रही हैं। इससे समाज के हर वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। यह पहल जिले में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। जशपुर जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 16,509 बुजुर्गों को नियमित सहायता मिल रही है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना से 4,356 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 656 दिव्यांगजन लाभान्वित हैं, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से 14,294 और सुखद सहारा पेंशन योजना से 4,407 हितग्राहियों को सहायता मिल रही है। सबसे अधिक लाभार्थी मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत हैं, जिसमें 40,244 लोग शामिल हैं। इसी प्रकार परिवार सहायता योजना के तहत 102 परिवारों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है, जिससे संकट की घड़ी में उन्हें संबल मिला है।

दिव्यांगजनों के लिए विभाग द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के तहत 180 विद्यार्थियों को सहायता दी गई है। दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना से 5 हितग्राहियों को लाभ मिला, जबकि कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना के अंतर्गत 290 दिव्यांगजनों को उपकरण उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा दिव्यांगजन सामर्थ्य विकास योजना से 550 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं तथा 'क्षितिज अपार संभावनाएं' योजना के तहत 4 दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया गया है।

जशपुर जिले में संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केन्द्र के माध्यम से अब तक 157 व्यक्तियों को नशामुक्त कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ा गया है। वहीं जशपुर नगर स्थित जनक वृद्धाश्रम में 12 वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित एवं सम्मानजनक जीवनयापन की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 782 वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर मिला है, जिससे उनके जीवन में संतोष और आध्यात्मिक सुख की अनुभूति हुई है।

खास खबर

निर्माणाधीन मकान में करंट लगने से युवक की मौत

कोरबा। कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के काशी नगर बुधवारी में एक निर्माणाधीन मकान में काम करते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे सामने आई। युवक को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान शहर के दादर बस्ती निवासी टीकाराम यादव (28) के रूप में हुई है। उसके भाई विकास यादव ने बताया कि, टीकाराम रोज की तरह सुबह काम पर निकला था। दो मंजिला निर्माणाधीन मकान में सरिया बिछाते समय वह ऊपर से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आ गया। मृतक के पिता भागीरथ यादव ने बताया कि, टीकाराम उनका सबसे छोटा बेटा था। घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए उसने शादी करने से इनकार कर दिया था। वह परिवार का कमाऊ सदस्य था, और उसकी मौत से परिवार के सामने बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है। इस मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में श्रम नियमों का उल्लंघन भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते नजर आए, जो श्रम कानूनों का सीधा उल्लंघन है। संबंधित विभाग पर केवल खानापूर्ति करने का आरोप लगाया गया है।

कार की टक्कर से बच्ची की मौत, शव रख सड़क जाम

जांजगीर। सक्ती जिले के फगुरम थाना क्षेत्र में बुधवार को तेज रफ्तार क्रेटा कार की टक्कर से 8 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने भदरी चौक के पास बच्ची का शव सड़क पर रखकर खरसिया-डभरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। हादसे में रिद्धिमा निराला पिता दानेश्वर निराला निवासी सारसकेला की मौत हो गई। बच्ची सड़क के पास खड़ी थी, तभी फगुरम निवासी अप्पू की क्रेटा कार क्रमांक सीजी बीडी 8433 लेकर चालक शत्रुघन यादव पहुंचा। उसने बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही सारसकेला और फगुरम के करीब 150 से अधिक ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर रास्ता पूरी तरह बाधित कर दिया। जाम के कारण दोनों ओर 30 से अधिक हाइवा, बस और चार पहिया वाहन फंस गए। वाहन मालिक के घर पर पथराव: हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सड़क तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीणों ने क्रेटा मालिक अप्पू अग्रवाल के फगुरम स्थित घर का घेराव कर पथराव किया। मौके का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक युवक कार की छत पर चढ़कर उसके शीशे तोड़ते दिख रहा है।

मोबाइल टॉवर की बैटरी चुराकर बेचते थे शातिर, पांच आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी। छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में पुलिस ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी करने वाले शातिर गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में मोबाइल कंपनी के दो कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से 93 बैटरी सहित 11 लाख से अधिक का मशरुका बरामद किया गया है।

पुलिस ने बताया कि मानपुर, खड़गांव, औंधी और कोहका थाना क्षेत्रों में लगे मोबाइल टावर से बैटरी चोरी होने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद टीम ने पतासाजी शुरु की। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 24 डब्ल्यू 9361 की पहचान हुई। वाहन चालक माखन तुमरेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में आरोपी हेमंत कुमार सिन्हा, भूपेंद्र रंगारी, माखन तुमरेटी, वीरेंद्र नेताम और देवराज बघेल को गिरफ्तार किया है। इनमें हेमंत सिन्हा और भूपेंद्र रंगारी खुद ही कंपनी के कर्मचारी है।

पिकअप के डाला पर लिखे मोबाइल नंबर से हुई पहचान

दरअसल पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही थी और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन करने पर पिकअप वाहन का फुटेज मिला। उसके डाला में दिए गए मोबाइल नंबर की तस्वीर कर आरोपी वाहन चालक माखन तुमरेटी निवासी दल्ली राजहरा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इस दौरान पता चला कि दल्ली राजहरा निवासी देवराज बघेल द्वारा जिओ कंपनी में काम करने वाले हेमंत सिन्हा निवासी कोरमटोला एवं भूपेंद्र रंगारी से मिलकर जिओ टावर के बैटरी चुराता था। चोरी की बैटरी को पिकअप में लोड कर भानु प्रतापपुर जिला कांकेर के कबाड़ी वीरेंद्र नेताम के पास बेच देता था। इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया।

जंगल में छिपाकर रखते थे बैटरी

चोरी करने के बाद बैटरी को कहडाबरी के जंगल में छिपाकर रखते थे। समय समय पर चोरी की बैटरी को भानुप्रतापपुर के कबाड़ी वीरेंद्र नेताम के पास बचते। देवराज बघेल के निशानदेही पर 93 नग बैटरी किमती करीबन 3 लाख 20 हजार रुपए बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त कार को कीमती 4 लाख रुपए, पिकअप वाहन क्रमांक- सीजी 24डब्लू 9361 को माखन तुमरेटी के पास से बरामद किया गया। कबाडी वीरेन्द्र के पास से 3 लाख 30 हजार की बैटरी पांच फोन सहित कुल 11 लाख 21 रुपए का मशरुका जब्त किया गया।

रायपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाते 2 आरोपी अरेस्ट, 5 लाख कैश और मोबाइल जब्त

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजधानी रायपुर में पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 5 लाख कैश और मोबाइल जब्त किए गए हैं। मामला कबीर नगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग रेलवे पटरी के पास मोबाइल के जरिए क्रिकेट मैचों पर सट्टा खिला रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दो लोगों को सट्टा संचालित करते हुए पकड़ा। पुलिस ने आकाश टांडी (31) और मोहम्मद आरिफ (50) के पास से कैश और मोबाइल बरामद किए। दोनों आरोपी कोटा के रहने वाले हैं। जब्त मोबाइल में सट्टा नेटवर्क से जुड़े अहम सबूत मिलने की संभावना है।

बड़े नेटवर्क से जुड़े तार

पूछताछ में आरोपियों से सट्टा नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और मुख्य संचालकों के बारे में अहम जानकारी मिली है। पुलिस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है।

जांच जारी, और गिरफ्तारियां संभव

पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है।

धमधा में महिला पर सूदखोरी-चेक दुरुपयोग का केस

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। दुर्ग जिले के धमधा क्षेत्र में सूदखोरी और चेक के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने गंडई निवासी शोभा केशकर उर्फ निशा (47) के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर मुसलमान पारा निवासी शहनाज बेगम (44) ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

शहनाज बेगम ने नवंबर 2023 में शोभा केशकर से 20 हजार रुपए उधार लिए थे। यह लेन-देन 10 प्रतिशत मासिक ब्याज दर पर हुआ था। सुरक्षा के तौर पर शहनाज ने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक कोरा चेक भी आरोपी को सौंपा था।

पीड़िता के अनुसार, उन्होंने करीब 9 महीने तक हर माह 2000 रुपए ब्याज के रूप में चुकाए। इस तरह मूल रकम से कहीं अधिक राशि चुकाने के बावजूद उनका कर्ज खत्म नहीं हुआ। आर्थिक तंगी के कारण जब शहनाज कुछ महीनों तक ब्याज नहीं दे पाईं, तो आरोपी ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जनवरी 2025 में शहनाज के भाई सादिक रजा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने 25 हजार रुपए में पूरा लेन-देन खत्म करने की बात तय करवाई। पीड़िता ने कुल मिलाकर लगभग 43 हजार रुपए चुका दिए।

इसके बावजूद आरोपी ने न तो चेक लौटाया और न ही लेन-देन समाप्त माना। शहनाज बेगम का आरोप है कि शोभा केशकर ने उनके दिए कोरे चेक का दुरुपयोग करते हुए उसमें 1 लाख रुपए की राशि भर दी। चेक बाउंस होने के बाद कोर्ट के जरिए उन्हें नोटिस भेजा गया, जिससे उन पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ गया।

पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया यह मामला अवैध सूदखोरी, धमकी और जबरन वसूली से जुड़ा पाया गया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी सुनियोजित तरीके से अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की ठगी कर रही है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए धमधा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली) और छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य पीड़ितों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

मां-बेटी ने नाबालिग संग मिलकर पति को मार डाला

रायपुर में लकड़ी के बैट से सिर पर हमला किया, मोबाइल को लेकर हुआ था विवाद

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजधानी रायपुर में मोबाइल को लेकर विवाद के बाद मां-बेटी ने एक नाबालिग के मिलकर पिता की हत्या कर दी। तीनों ने लकड़ी के बैट और ईंट से सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों को अरेस्ट कर लिया है।

मामला डीडी नगर क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 29 सितंबर 2025 को वीरेंद्र भारती गोस्वामी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वीरेंद्र के शरीर पर 17 गंभीर चोटें पाई गईं, जिससे हत्या की पुष्टि हुई।

डीसीपी पश्चिम संदीप पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने जांच की। पूछताछ में पत्नी, बेटी और

नाबालिग ने हत्या करना कबूल किया। पूछताछ में सामने आया कि 27 सितंबर 2025 की रात करीब 11 बजे मोबाइल देखने को लेकर घर में विवाद हुआ था।

वारदात के बाद लकड़ी और ईंट नाले में फेंका

गुस्से में आकर तीनों ने लकड़ी के बैट और ईंट से वीरेंद्र के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। वारदात के बाद तीनों ने खून साफ किया और वारदात में इस्तेमाल लकड़ी और ईंट को पास के नाले में फेंक दिया।

लोगों को गुमराह करने झूठी कहानी बनाई

इसके बाद परिवार के अन्य लोगों को गुमराह करने के लिए यह कहानी बनाई गई कि वीरेंद्र बाथरूम में गिरकर बेहोश हो गया था। इस मामले में पुलिस ने दीपा भारती गोस्वामी (44), तनिया भारती गोस्वामी (19) और नाबालिग लड़की को अरेस्ट किया है।

न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

मामले में डीडी नगर थाना में अपराध क्रमांक 252/2026 के तहत धारा 103(1), 238, 3(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है, जबकि मां-बेटी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

ठगी करने वाले कॉल सेंटर गिरोह का मास्टरमाइंड गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। रायपुर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी करने वाले अवैध कॉल सेंटर गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड विकास नरेंद्र शुक्ला को महाराष्ट्र के शोलापुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगातार छापेमारी की जा रही थी।

इससे पहले 25 मार्च 2026 को पुलिस ने इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन में बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग अवैध कॉल सेंटरों पर रेड मारी थी। इस दौरान सुपरवाइजर समेत कुल 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गंज और न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिथालिया कॉम्प्लेक्स और अंजनी टावर में संचालित

कॉल सेंटरों पर छापा मारकर पुलिस ने 67 मोबाइल, 18 लैपटॉप, 28 कंप्यूटर सेट और 3 वाई-फाई राउटर जब्त किए थे। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 16.53 लाख रुपए बताई गई थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मास्टरमाइंड के रूप में विकास शुक्ला का नाम सामने आया, जिसके बाद तकनीकी विश्लेषण कर उसकी लोकेशन ट्रेस की गई और उसे शोलापुर से गिरफ्तार कर लिया गया।

डार्क वेब से डेटा, गिफ्ट कार्ड से ठगी

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह अपने साथियों के साथ डार्क वेब के जरिए अमेरिकी नागरिकों का डेटा खरीदता था। यह डेटा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वेंडर्स से लिया जाता था। इसके बाद कॉल सेंटर से लोगों को लोन और क्रेडिट स्कोर सुधारने के नाम पर झांसा देकर गिफ्ट कार्ड के जरिए पैसे वसूले जाते थे। जो लोग पैसे नहीं देते थे, उन्हें फर्जी वारंट और नोटिस भेजकर डराया जाता था।

क्रिप्टो के जरिए होता था लेन-देन

ठगी से मिली रकम को प्रोसेसिंग चैनल के जरिए (क्रिप्टोकरेंसी) से भारतीय मुद्रा में बदला जाता था। इसमें कमीशन काटकर रकम गिरोह के सदस्यों में बांटी जाती थी।

आरोपी पहले भी जा चुका है जेल

पुलिस के मुताबिक विकास शुक्ला मूल रूप से अहमदाबाद (गुजरात) का रहने वाला है और साल 2019 में पुणे में अवैध कॉल सेंटर चलाकर ठगी करने के मामले में जेल जा चुका है।

गिरफ्तारी में ये सामान बरामद

आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड,1 पैन कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

ओवरलोड पिकअप पलटी 2 की मौत, 17 लोग घायल

रायगढ़। लैलूंगा थाना क्षेत्र के मटिया कछार गांव के करीब 30 ग्रामीण मंगलवार की शाम चिंगारी बाजार से खरीदारी कर लौटते समय पिकअप में लिफ्ट लेकर सवार हो गए। रास्ते में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है।

मटिया कछार के करीब 30 महिला-पुरुष व बच्चे चिंगारी गांव के बाजार खरीददारी के लिए गए थे। लौटते समय सभी ने एक पिकअप वाहन में लिफ्ट ली। पिकअप को चालक राजू डनसेना चला रहा था। शाम करीब 7 बजे पत्ताफाड़ी आमरोड के पास पहुंचते ही वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और सभी सवार घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, डायल 112 और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को तत्काल लैलूंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान छतिया यादव (45) और भूपदेव राम राठिया (50), दोनों निवासी मटिया कछार की मौत हो गई। वहीं 6 महिलाएं, 6 पुरुष, 1 बालक और 4 बालिकाएं घायल हैं, जिनका उपचार जारी है।

ओवरलोड होने से वाहन का संतुलन: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप वाहन ओवरलोड था, जिसके कारण चालक संतुलन खो बैठा।

पीरियड्स के दौरान 13 साल की नाबालिग से रेप, 20 साल की कैद

परिवार को जान से मारने की धमकी दी, दोस्त के कमरे में वारादत

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राजधानी रायपुर में 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप को आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी युवक ने दोस्त के कमरे में वारदात को अंजाम दिया था। मामला दिसंबर 2024 का है, जो खरोरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

जानकारी के मुताबिक युवक ने नाबालिग को जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके परिवार को मार डालेगा। वारदात के दौरान नाबालिग का पीरियड्स चल रहा था।

वारदात के 5 महीने पहले हुई थी मुलाकात

दरअसल सोनू चेलक (20) और नाबालिग की मुलाकात करीब पांच महीने पहले हुई थी। दिसंबर 2024 में नाबालिग अपनी दादी

के गांव गई हुई थी। 14 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे नाबालिग दुकान जाने के लिए घर से निकली। इसी दौरान आरोपी बाइक से वहां पहुंचा और उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा, लेकिन नाबालिग ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी उसे धमकाने लगा और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण नाबालिग उसके साथ बाइक पर बैठ गई।

दोस्त के कमरे में किया रेप

आरोपी नाबालिग को रायपुर के डूमरतराई में अपने दोस्त के कमरे में ले आया, फिर वहां जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान नाबालिग ने विरोध किया, लेकिन आरोपी नहीं माना और वारदात को अंजाम दिया। इस बीच पीड़िता के पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपी को घर से किया गिरफ्तार

पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की। वारदात के अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को गांव में छोड़ दिया। पीड़िता ने घर आकर परिवार को पूरी घटनाक्रम बताई। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को घर से गिरफ्तार किया।

मेडिकल रिपोर्ट बना सबूत

मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में रायपुर जिला कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया है।

बिलासपुर में डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक सिगरेट पकड़ाया

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक कंपनी की सिगरेट का भंडाफोड़ हुआ है। व्यापार विहार स्थित मालधक्का में नकली सिगरेट की सप्लाई हो रही थी। दिल्ली आईटीसी की टीम ने ग्राहक बनकर नकली सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी है। व्यापार विहार इलाके में एक व्यापारी के पास से करीब 5 लाख रुपए की 4 कार्टून सिगरेट बरामद किया गया है। यह कारोबारी शहर में छोटे-बड़े दुकानदारों को थोक में सिगरेट सप्लाई कर रहा था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।

दरअसल, दिल्ली की आईटीसी को पहले ही सूचना मिली थी कि, शहर में नकली सिगरेट की सप्लाई हो रही है। जिस पर बुधवार को टीम के सदस्य बिलासपुर पहुंचे। पहले उन्होंने पान-ठेलों से सैंपल लिए और सिगरेट की जांच की। जिसमें दुकानों में बिक रहे सिगरेट नकली पाए गए। टीम के सदस्यों ने दुकानदारों से सिगरेट की सप्लाई की जानकारी ली।

जिसके बाद टीम के सदस्यों ने ग्राहक बनकर सिगरेट की डिमांड की। इस दौरान कारोबारी ने उन्हें महाराणा प्रताप चौक स्थित निगम कॉलोनी के पास बुलाया। जहां थोक सप्लायर रोशन चंदानी की फर्म में आने की जानकारी दी। इस पर टीम के सदस्य सीधे रोशन चंदानी की दुकान पहुंच गए। टीम के सदस्यों ने यहां सिगरेट की जांच की और ओरिजनल पैकेट और स्टिक से मिलान किया। जिसमें दुकान का माल नकली निकला।

पुलिस को बुलाकर जब्त कराया 5 लाख का सिगरेट

इसके बाद टीम के सदस्य सिविल लाइन थाने पहुंचे। जब्त माल को भी थाने ले जाया गया। यहां देर रात तक पुलिस की कार्रवाई चलती रही। टीआई एसआर साहू ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है, जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि नकली सिगरेट का यह कारोबार रोजाना 2 लाख रुपए से ज्यादा का है। वहीं, असली और नकली की पहचान पैक की प्रिंटिंग, होलोग्राम, कोड, स्टिक की बनावट और स्वाद से की जाती है। शहर के छोटी दुकानों में यहां से सिगरेट की सप्लाई की जाती है। शहर में नकली सिगरेट का खेप पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही कारोबारी रोशन चंदानी के परिचित व्यापारी सिविल लाइन थाना पहुंचने लगे। देर रात तक यहां व्यापारियों की भीड़ जुटी रही। बताया जा रहा है कि कुछ व्यापारी उसे छोड़ने के लिए दबाव भी बना रहे थे।

ट्रेन को क्षति पहुंचाने ट्रैक पर लोहा रखने वाला गिरफ्तार

राजनांदगांव। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल के अंतर्गत ट्रेन को क्षति पहुंचाने रेलवे ट्रैक पर लोहा रखने वाले आरोपी को आरपीएफ डोंगरगढ़ ने गिरफ्तार किया है। इंजन के ऑयल टैंक को नुकसान पहुंचाने का खुलासा किया गया। गाड़ी संख्या 12856 इतवारी-बिलासपुर एक्सप्रेस का इंजन परमालकसा के मध्य किमी संख्या 891/6 पर एक जुगल प्लेट इंजन के नीचे लोहा टकराने से इंजन का ऑयल टैंक क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की गंभीरता को देख आरपीएफने डोंगरगढ़ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। धारा 153, 174 (बी) एवं 147 रेलवे अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर जांच की। ग्राम पारीनाला में एक घर पर दबिश दी। पूछताछ के दौरान एक बालक, पारीनाला यादव उम्र लगभग 15 वर्ष निवासी पारीकला को चिन्हित किया गया।

प्रमुख खबरें

मुख्यमंत्री साय ने पुलिस अफसर मेस का किया लोकार्पण

सुकमा। जिले के पुलिस अधिकारियों को बेहतर आवासीय एवं भोजन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस लाइन सुकमा में पुलिस अफसर मेस का लोकार्पण किया। मेस लगभग 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह आधुनिक मेस पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और सुविधाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों और पुलिस अधिकारियों की सुविधाओं का ध्यान रखना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में महिला आयोग सदस्य दीपिका सोरी, वरिष्ठ पार्टी प्रतिनिधि धनीराम बारसे, जिला पंचायत सदस्य कोरसा सन्नू, जिला पंचायत सदस्य हुंगाराम मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष सुकमा हुंगाराम मरकाम अन्य जनप्रतिनिधि सहित कमिश्नर डोमन सिंह, आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण, सीईओ जिला पंचायत मुकुन्द ठाकुर, डीएफओ अक्षय कुमार भोंसले उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ केबिनेट की अहम बैठक में लिए गए कई निर्णय

छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा 'यूनिफॉर्म सिविल कोड', समिति गठित

श्रीकंचनपथ समाचार

नवा रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुख निर्णयों में छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविर कोड) लागू करना, महिलाओं के नाम पर संपत्ति का पंजीयन होने पर रजिस्ट्री में 50 फीसदी की छूट दिया जाना तथा सैनिक एवं पूर्व सैनिकों को रजिस्ट्री में 25 फीसदी छूट देना शामिल है।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code लागू करने के संबंध में प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर Uniform Civil Code का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान और पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित हो सके।

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आबंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी।

भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखण्डों हेतु एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है।

NBFC सहित वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यावहारिक स्पष्टता आएगी और Ease of Doing Business सुनिश्चित होगा। PPP मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025

अब केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे एकाधिकार से उत्पन्न रेत आपूर्ति-संकट में कमी आएगी। दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों का सुगम संचालन सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है, अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है। गौण खनिज की ऐसी खदाने जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है, में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षों के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यपगत (लैप्स) घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किये जाने की बाध्यता सुनिश्चित हो सकेगी। खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रूपए होगी।

छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करना इसलिए जरूरी

वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत करने UCC लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।

महिलाओं को जमीन की रजिस्ट्री में छूट

मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तीकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है।

सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों को भी रजिस्ट्री में छूट

राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रूपए तक की संपत्ति (भूमि/भवन) क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्राय: स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वे स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं, ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा।

बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने कालेजों में अब लागू होगा 'रक्षक' पाठ्यक्रम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राज्य में 'रक्षक पाठ्यक्रम' को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में बाल संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है।

इस पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े तथा उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा के सहयोग से एमओयू हो चुका है। संपन्न किया गया था।

बुधवार को 'रक्षक' पाठ्यक्रम के अंतर्गत तैयार उप-इकाइयों को अंतिम रूप देने हेतु विश्वविद्यालय स्तरीय परामर्श बैठक आयोजित की गई।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि रक्षक पाठ्यक्रम केवल एक शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक सामाजिक अभियान है। प्रयास है कि इसे प्रभावी रूप से लागू कर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित और जागरूक बनाया जाए।

बैठक में राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों—पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी और अंजनेय यूनिवर्सिटी—के कुलपति, कुलसचिव, प्रतिनिधि एवं विषय विशेषज्ञ शामिल हुए।

इस दौरान विशेषज्ञों ने पाठ्यक्रम की संरचना, उपयोगिता और व्यवहारिक पहलुओं पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए। विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों ने इस पहल को समय की आवश्यकता बताते हुए आयोग की सराहना की और इसके सफल क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

वनौषधि हर्रा प्रसंस्करण से महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर, बना रहीं आठ उत्पाद

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाय) ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव और आर्थिक सशक्तिकरण की एक माध्यम बन गई है। ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से, यह योजना स्थानीय वन उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के माध्यम से महिलाओं को उद्यमी बना रही है।

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित कांकेर के अंतर्गत संचालित वनधन योजना ने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। इच्छापुर का हर्रा वनौषधि प्रसंस्करण केन्द्र आज महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है।

वनधन विकास केन्द्र इच्छापुर की स्थापना के बाद मर्दापोटी कलस्टर के 17 गांवों के 2137 परिवार इससे जुड़े हैं। इनमें से 1512 परिवार लघु वनोपज संग्रहण के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा खनिज विकास निधि से मशीन, पैकेजिंग सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए, जिससे प्रसंस्करण केन्द्र का संचालन शुरू हो सका। इस केन्द्र का संचालन इंदिरा वन मितान स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

समूह की महिलाएं अब वनौषधियों का संग्रहण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग का कार्य कर रही हैं। केन्द्र में हर्रा, बहेड़ा, त्रिफला, अश्वगंधा, सफेद मूसली, नीम, सतावरी और आंवला चूर्ण सहित 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानकों के अनुसार पैकेजिंग की जाती हैद्य महिलाओं को समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आयुर्वेद विभाग और राज्य संघ द्वारा तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950